Haryana Vidhan Sabha

Debates

16th February, 1971

(Morning sitting)

Vol. 1 – No. 8

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 16th February, 1971 (Morning sitting)

Postponed Starred Question and Answer	(8) 1
Starred Question and Answer	(8) 14
Written Answer to Starred Questions laid on the Table under Rule 45	(8) 28
Short Notice Question and Answer	(8) 31
Call Attention Notice	(8) 53
Demands for Grants	(8) 59
Voting on Demands for Grants	(8) 99
Annexure	

Haryana Vidhan Sabha

Tuesday, the 16th February, 1971

(Morning sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha. Vidhan Bhavan: Chandigarh: at 9.30 A.M. of the Clock, Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

POSTPONED STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker: Honourable Members, the Question Hour.

Expenditure on Prime Minister's Visit to Uchani

***1148. Shri Randhir Singh**: Will the Chief Minister be pleased to State the total expenditure incurred on the recent visit of the Prime Minister to Village Uchani, District Karnal, in the Haryana State.

Chief Minister (Shri Bansi Lal): The expenditure incurred by the State Government on the Prime Minister's Visit to Village uchani was Rs. 20,653. This was in connection with the normal Security arrangements which have necessarily to be on such occasions.

श्री रणधीर सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस रोज प्रधानमंत्री आई थीं उस दिन कितने ट्रक, जीपें, व दूसरी गाड़ियां लगाई गई और कुल कितना खर्चा हुआ?

Mr. Speaker: You have put your question from the porsponed List, but you should have started with your question from the Regular List for today.

श्री बंसी लाल: आनरेबल मेम्बर ने पूछा कि प्रधान मंत्री के आने पर कितनी कारें, जीपें तथा दूसरी गांडियां लगाई गई है। सरकार ने न कोई कारें लगाई, न ट्रक लगाए और न कोई जीपें ही लगाई थी।

Mr. Speaker: You are giving reply to the question on the Postponed list, whereas we should have first taken up the regular list.

श्री बंसी लाल: आनरेबल मेम्बर ने सवाल पूछ ही लिया है तो इन्हें और प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

श्री रणधीर सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि उस रोज बिजली बोर्ड ने कितना खर्च किया था?

श्री बंसी लाल: बिजली बोर्ड का जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब हमारे पास नहीं आया है।

I have already given the figures of expenditure on the security arrangement made for the Prime Minister. These

are the arrangements which are normally made for the Prime Minister.

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न यह था कि प्राईम मिनिस्टर के आने पर कुल कितना खर्चा हुआ। मैंने यह नहीं पूछा कि सिक्योरिटी पर कितना खर्चा हुआ। मेरे प्रश्न में, सिक्योरिटी, बिजली बोर्ड तथा एंटरटेनमेंट का कुल खर्चा शामिल है।

श्री बंसी लाल: बिजली बोर्ड के खर्चे के सम्बन्ध में अलग प्रश्न पूछना चाहिए।

This question concerns the expenditure on the security measures made by the State Government for the security of the Prime Minister. So far as I see the expenditure of the Electricity Board may not be high.

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुख्यमंत्री महोदय स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और जो भी खच्र होता है वह उनकी आज्ञा से होता है और बिजली बोर्ड भी उन्हीं के मातहत है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो बिजली बोर्ड ने खच्र किया वह उन्हीं की आज्ञा से हुआ है या नहीं?

श्री बंसी लाल: मेरे मातहत तो सारे ही महकमें आते हैं। इस प्रान्त के सारे खर्चे विधान सभा की आज्ञा से होते हैं अकेले मुख्यमंत्री की आज्ञा से नहीं।

श्री रणधीर सिंह: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रधान मंत्री पर खच्र हुआ है वह विधान सभा में पारित हो चुका था?

श्री बंसी लाल: जरूर हो चुका था और अगर नहीं हुआ तो वह इस बजट में आ जाएगा।

चौ. दल सिंह: ऐसा सुना गया है कि जिस दिन प्रधान मंत्री आई थीं उस रोज हजारों रूपए की शराब पी गई थी। क्या यह दुरूस्त है और अगर दुरूस्त नहीं है तो क्या सरकार इसको कन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेगी?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, सरकार की नालिज में तो नहीं है कि उस दिन शराब पी गई थी अगर चौ. दल सिंह या इनके सिकी आदमी ने पी हो तो ये सूचना दे दें।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री जिस काार में देहली से आई उसका किसने इंतजाम किया था?

श्री बंसी लाल: कार की बात तो मैं नहीं बता सकता कि किसने उसका इंतजाम किया था। बिजली बोर्ड ने उसका इन्तजाम किया होगा या सिक्योरिटी वालों ने किया होगा।

But, the details are not with me. However, the figures of total expenditure have been given.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब मेरी इतलाह के मुताबिक वह कार (व्यवधान) दिल्ली की एक प्राईवेट कम्पनी की थी। पिछली दफा जब प्राईम मिनिस्टर यहां चंडीगढ़ आई थीं तो चीफ मिनिस्टर साहब उनकाो एक खुली जीप में अपनी कोठी ले गये थे। उन्होंने यह शिकायत की थी कि इसमें बैठने से तो उनके पेट के पुर्जे हिल गए। इसलिए अब की दफा दिल्ली की फर्म को आर्डर दिया गया था। वह कार बिजली बोर्ड ने किराए पर ली थी।

श्री अध्यक्ष: वह तो एक ही बात होगी चाहे किराए पर सरकार ले या बिजली बोर्ड।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: कम से कम जनता को पता चले कि ये जो सोशलिज्म का नारा लगाते हैं, उसका पाललन कितना किया जाता है। ये खाली सोशलिज्म का प्रचार करते हैं लेनिक उस पर अमल जरा भी नहीं किया जाता। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I am afraid, it is too early in the day to start such things in this sitting. Today, we are also having the second sitting will be non-stop.

श्री फतेह चन्द विज: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस खर्चे के अन्दर प्रधानमंत्री को जो थैली दी गई है वह रकम भी शामिल है?

श्री बंसी लाल: वह तो जनता का पैसा था, जनता ने प्रधान मंत्री जी को भेंट किया था खजाने से कोई पैसा नहीं दिया गया।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: मुख्यमंत्री ने जो थैली प्रधान मंत्री को भेट की .....

श्री बंसी लाल: वह थैली मैंने भेंट नहीं की बल्कि पी. सी.सी. प्रैजीडेन्ट ने की थी।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: क्या मुंख्यमंत्री वह लिस्ट देने के लिए तैयार है कि किसने कितना रूपया दिया है?

श्री बंसी लाल: यह तो पार्टी का मैटर है। वैसे भी किसी ने एक रूपया दिया, किसी ने दस रूपये दिए तो यह सब हिसाब कैसे रखा जता सकता है?

चौ. जय सिंह राठी: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएगे कि प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए कितने गेट बनाए गए थे और उन पर कितना खर्चा हुआ?

श्री बंसी लाल: गेट बहुत ज्यादा थे, वे 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। जहां तक खर्चे का सवाल है वह तो जनता ने बनाए, जनता का ही खर्चा हुआ है।

श्री रणधीर सिंह: क्या मुख्यमंत्री यह बताएंगे कि ये गेट बिजली बोर्ड ने बनवाए थे और जो खर्चा इन पर किया गया वह भी बिजली के बोर्ड ने किया है?

श्री बंसी लाल: एक आध गेट बिजली बोर्ड ने बनवाया होगा। सब गेट जनता की तरफ से बनाए गए थे। प्रधानमंत्री जनता की पापूलर लीडर हैं और पापूलर लीडर का स्वागत होता ही है। इनके पास तो चले हुए कारतूस हैं। जब मुरार जी देसाई करनाल में आए थे तेा उनकी मीटिंग में 450 आदमी थे। (व्यवधान)

चौ. जय सिंह राठी: क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली बोर्ड ने जो खच्र किया वह किस आईटम पर किया है?

श्री बंसी लाल: उसका अलग से नोटिस दिया जाए तो वह बताया जा सकता है।

Started Question No. 1056*

Mr. Speaker: We go to the next Question. Shri Randhir Singh please.

Shri Randhir Singh: Question No. 1156, Sir.

Mr. Speaker: Now, I want to mention about this that although this question was included in the list of postponed questions for today with the concurrence of the hon. Minister concerned., again the reply to this question has

not been received. The hon. of member will get the reply to his question. Next question please.

Setting up of Small Scale Industries

***1157. Shri Randhir Singh**: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the total number of small scale industries set up in villages during the year 1968-69 and 1969-70 together with the number of such villages; and

(b) the percentage of people who have found job in the industries referred to in part (a) above?

Industries Minister (Shri Abdul Ghaffar Khan):(a)

(i) Total number of small units set up in the villages which are registered with the department of Industries are as under:-

Year	Registered Units	No. of Villages.
1968-69	40	31
1969-70	65	45

(ii) Collection of information of un-registered units is not commensurate with the efforts involved.

(b) Not possible to give in view of (a) (ii) above.

श्री रणधीर सिंह: क्या उद्योग मंत्री साहब बताएंगे कि यह यूनिट कहां–कहां और किस–किस गांव में लगाए गए हैं?

Sh. Abdul Ghaffar Khan: Sir, I am going to read out lists giving district-wise number of industries in the villages, viz, -Ambala.

1968-69			1969-70		
No. of Units	Persons employed	No. of villages.	No. of Units	Persons employed	No. of villages.
Regd. 9	82	6	Regd. 5	39	5

श्री रणधीर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने तो यह पूछा ाि कि किस किस गांव में ये यूनिट खड़ी की गई है।

Sh. Abdul Ghaffar Khan: I am going to give a lengthy list and then the Hon. Member will ask for laying it on the Table.

श्री रणधीर सिंह: स्पीकर साहिब मेरा सवाल तो बहुत कलियर था, मैंने तो पूछा था कि किन किन गांव में इन्होंने यह यूनिटस एस्टेबलिश की हैं। खान साहिब को उसका जवाब देना चाहिए।

Mr. Speaker: The information has been given in the answer that total number of villages where industries have been set up is seventy six.

Sh. Randhir Singh: Sir, I have asked for the names of the Villages where the industries have been set up.

Sh. Abdul Ghaffar Khan: With your permission, I am going to read the names of the Villages before the House They are :-

District Ambala (1968-69)

Sadhaura.

Sadhaura.

Sadhaura.

Sadhaura.

Sadhaura.

Sadhaura.

Sadhaura.

Raipur Rani

Sadhaura.

Chhachrauli.

Machauda.

Uddamgarh.

Dhiano.

Dadupur.

Bilaspur.

Dhiano.

Ch. Jai Singh Rathi: Sir, I will submit before you that not a single word is either audiable or understandable.

Mr. Speaker: I am listening it all right. (Interruptions)

Sh. Abdul Ghaffar Khan: Sir, I was quoting the names of the villages in Ambala District. Further the names of the Villages are:-

1969-70.

Bhin.

Sohna.

Bilaspur.

Naraingarh.

Mustafabad.

Mustafabad.

Mustafabad.

Mustafabad.

Mustafabad.

Deodhar.

Chhachrauli.

Naharpur.

Naharpur.

Naharpur.

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय यह एक लम्बी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि बजाए इसके कि सदन का टाईम खराब किया जाए बेहतर यह होगा कि वह इसको सदन के टेबल पर रख दें। अगर उन्होंने पहले ही इसको हाउस के टेबल पर रखा हुआ है तो फिर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और अगर उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया तो अब रखे दें।

Mr. Speaker: He has asked for the list of villages to be read. (Interruptions)

Incidentally let me find out if the hon. Members has got the list of villages?

Sh. Randhir Singh: No. Sir.

Mr. Speaker: So, the list of villages has not been laid on the table of the House and the hon. Member has asked the list of the villages to be announced. If he says that he does not want it then the hon. Minister will not give it.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब उन गांव की लिस्ट तो सौ या डेढ सौ के करीब होगी, इसलिए इसको पढ़ने में बहुत

टाईम लग जाएगा। तो पढ़ने की बजाए वह इसको टेबल पर रख दें।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब मैंने खुद कहा था कि यह 76 गांव हैं लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाम चाहता हूं, तो इसलिए वह पढ़ रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि सढौरा में किस किस किस्म की इंडस्ट्री है?

Sh. Abdul Ghaffar Khan: I am reading afresh from the Ambala District, the industries set up there are, viz, -

1. Tanning Leather.

2. Tanning Leather.

3. Tanning Leather.

4. Tanning Leather.

5. Tanning Leather.

6. Tanning.

7. Tanning.

8. Shoe making,

9. Cement Jallies.

10. Soap.

11. Shoe making.

12. Poultry.

13. Carpentary.

14. Welding.

15. Soap making.

16. Carpentary.

श्री रणधीर सिंह: स्पीकर साहब वह सिर्फ करनाल के जिला की लिस्ट पढ़कर सुना दे, वही काफी होगी।

श्री अध्यक्ष: खान साहब आप सिर्फ करनाल की ही बता दीजिए।

श्री अब्दुल गफ्फार खान: जनाब स्पीकर साहब जब करनाल का नम्बर आएगा तो मैं उसका भी बता दूंगा। जब इन्होंने सवाल इतना लम्बा चौड़ा किया है तो फिर वह मुझे जवाब भी बता लेने दें।

The other industries are –

17. Carpentary.

18. Shoe.

19. Shoe.

20. Durries.

21. Aluminium Utensils.

22. Agricultural implements.

23. Agricultural implements.

24. Aluminium Utensils.

25. Ayurvedic medicines.

श्री रणधीर सिंह: मैंने गांव के नाम पूछे हैं और वजीर साहब इन्डस्ट्रीज के नाम बता रहे हैं ..... (शोर) .....

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): एक मैम्बर साहब ने इन्डस्ट्रीज के नाम के बारे में भी पूछा है और वह बात रहे हैं ..... (शोर) .....

Mr. Speaker: Let us clear this aspect. Smt. Chandravati Ji had asked about the type of industries set up at Sadhaura and other Places which your have given. Now. the hon. Member who has asked this question wants to know the names of village in Karnal district where industries have been set up.

Sh. Abdul Ghaffar Khan: I had started giving you information beginning form the Ambala District. He wants to ignore Ambala district Why should I leave it in between and go to Karnal district?

Mr. Speaker: He does not want to ignore Ambala District. He thinks that there are a large number of industries. He wants to know about Karnal district.

श्री अब्दुल गफ्फार खान: करनाल के बारे में भी बता देता हूं मेरे पास पहले हिसार की लिस्ट शुरू होती है अगर कहो

तो पहले वहां से शुरू कर दूं। (हंसी) ....(शोर).... अच्छा पहले करनाल के बारे में बता देता हूं शोर क्यों करते हो।

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यह लिस्ट टेबल पर रख दें। मैं इसमें से नाम देख लूंगा। (विघ्न)

Sh. Abdul Ghaffar Khan: Now, I will read the names of villages in the Karnal District. They are –

1. Cheeka.

2. Cheeka.

3. Cheeka.

4. Cheeka.

5. Cheeka.

6. Cheeka.

7. Cheeka.

8. Cheeka.

9. Guhla.

10. Guhla.

11. Guhla.

12. Guhla.

13. Bhogal.

14. Tanner.

15. Tanner.

16. Tanner.

17. Tanner.

18. Dewana.

19. Khanaudi.

20. Khangthali.

21. Sewan.

22. Sewan.

23. Cheeka.

24. Cheeka.

25. Cheeka.

26. Cheeka.

27. Cheeka.

28. Cheeka.

29. Cheeka.

30. Cheeka.

31. Cheeka.

32. Cheeka.

33. Cheeka.

चौ. जय सिंह राठी: यह पढ़ क्या रहे हैं हमें न कुछ सुनता है और न समझ आ रहा है कि वह क्या पढ़ रहे हैं (शोर)

Sh. Abdul Ghaffar Khan: I am reading out the names of those villages where industries are located. Different industries, have been set up in different villages or in the same village. I am reading out the names of those villages.

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय मै। संतुष्ठ हो गया हू कि करनाल में भी कहीं कहीं इन्डस्टरीज लगी हैं। बाकी जो लिस्ट है वह टेबल पर रख दी जाये और अब सप्लीमेंटरी होने चाहिये।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जिला हिसार के किस किस गांव में किस किस किस्म की इन्डस्टरीज लगी हैं?

Sh. Abdul Ghaffar Khan: When I am reading out the names of villages, it is being said that the list should be laid on the Table of the House ..... (Interruptions)

Mr. Speaker: Any way, Khan Sahib does not wish to answer that question. So, we go to the next question.

Sh. Bansi Lal: He is ready. He is giving the information.

Sh. Abdul Ghaffar Khan: I do want to reply and satisfy the hon. Members by my reply. But when I am reading out the information, they disturb me. I will now read out the names in the Hissar district.

1 Dobbi

2 Paluwas.

3 Kurri.

4 Kurri.

5 Kurri.

6 Kurri.

7 Kurri.

8 Ellenabad

9 Dhana Khurd

10 Tatera

11 Sorkhi

12 Jamalpur.

13 Chang.

14 Chang.

15 Bawani Kheri.

16 Kurri.

17 Badopal.

18 Tiggrana

19 Sandwa.

20 Bapora.

21 Ladwa.

22 Asalwas.

23 Asalwas.

24 Bapora.

25 Bahuna.

26 Chang.

27 Bag AZamshahpur.

28 Moth Rangharan.

29 Madanheri.

30 Rakhi Khas.

31 Rakhi Shahpur.

32 Sodhwas.

33 Naina.

34 Bisalwas.

35 Nehla.

36 Moda Khera.

37 Dhana Khurd.

38 Rawalwas Khurd.

Year 1969-70.

1. Barwala.

2. Kurari.

3. Kirthan.

10.00 A.M.

श्री अध्यक्ष: खान साहब, आपने जवाब में 76 गांव बतायें थे लेकिन 76 गांव तो आपने हिसार डिस्ट्रिक्ट के ही पढ़ दिए हैं। (हंसी)

श्री अब्दुल गफ्फार खान: स्पीकर साहब, मैं अपने महकमें के मुताल्लिक सारी इत्तलाह लेकर आता हूं। जब इन्होंने पूछा तो मैंने नाम पढ़ने शुरू किए हैं लेकिन यह अब बातें बनाने लगे हैं .....

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल दुरूस्त है। Thank you very much.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker: Now, we will start-with the list of starred Question for today.

BORING RIGS

***1118. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state:

(a) the total number of boring rigs in the State as on 1-1-191;

(b) the number out of those which are in working order;

(c) the district-wise break up the performance of these rigs;

(d) whether there is any deep boring rigs in Jind district;

(e) if so, substantial gain, if any, that has accrued through these rigs in Jind district; and

(f) the manner in which the government propose to effectively make use of the rigs in Jind district so as to find out underground sweet water?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल):

(क) 26

(ख) 24

(ग) ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध न. 1 में दिया गया है।

(घ) नहीं।

(ड.) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी सेंट्रल ग्रांउंड वाटर बोर्ड (भारत सरकार) द्वारा जीन्द में 4 सर्वेक्षण (एकसप्लोरेटरी) बोर होल किए जिनमें से एक ही सफल हुआ है।

(च) आगामी कार्यक्रम इस प्रकार है कि पहले सफीदों, जीन्द, राजथल और मढ़ा में उपलब्ध मीठे पानी की कुल मात्रा का अनुमान लगाा जाएगा और जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो जिला जीन्द में अतिरिक्त गहररे बौर किए जायेंगे।

अनुबन्ध।

जिलो में रिग मशीनों के विवरण तथा उनके कार्य की व्यवस्था

जिले का नाम	चालू रिंग मशीनों की संख्या	सफल बोरों की संख्या	असफल बोरों की संख्या	कुल
अम्बाला	* 4	59	3	62
करनाल	* 2	19	1	20
जीन्द	2	18		18
हिसार	5	43	6	49
रोहतक	1	24	2	26
महेन्द्रगढ़	4	51	8	59
गुड़गावां	6	61		61

* नोटः– माईनर इरीगेशन कारपोरेशन की चार रिंग मशीनें एक गुड़गावां, एक करनाल तथा बाकी दो अम्बाला जिले में कार्य कर रही हैं।

श्री दया कृष्ण: क्या वजी साहब यह महसूस नहीं करते कि जीन्द डिस्ट्रिक्ट के लिए दो रिंग नाकाफी हैं?

श्री भजन लाल: अगर और जरूरत महसूस हुई तो और रिंग भेज दैंगे।

चौ. रणबीर सिंह: क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि रोहतक जिले में सिर्फ एक ही रिंग है जबकि तमाम सूबे के औस्तन बोर की संख्या रोहतक जिले में सबसे अधिक है। इन्होंने सवाल के जवाब में बताया है कि रिंग एक ही और बोर 26 किए गये। रोहतक जिले में ज्यादा रिग क्यों नहीं दिए गए? क्या वहां ज्यादा रिंग देने का इरादा है?

श्री भजन लाल: दूसरी जगहों पर काम हो रहा है। जब वहां काम खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगहों पर भेज दी जायेंगी।

चौ. लाल सिंह: मेरे इलाका जमीन पत्थर वाली है इसलिए जो रिग वहां भेजी गई हैं वे काम नहीं कर रही हैं। क्या सरकार वहां पत्थर काटने वाली रिंग भेजेगी?

श्री भजन लाल: मशीनें जल्दी आने वाली हैं, जब आ जायेगी तो भिजवा दी जाएंगी।

चौ. लाल सिंह: जबकि 200 टयूबवैल्ज लगने वाले हैं तो क्या इन दो सौ टयूबवेल्ज के लिए एक ही बोरिंग मशीन काफी हो सकती है?

श्री भजन लाल: जरूरत के मुताबिक और भिजवा दी जाएंगी।

Total Land Irrigation by Yamuna and Bhakra Canals

***1162. Sh. Randhir Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the acreage of land being irrigated by the Yamuna Canal and the Bhakra Canals, separately, in the State, District-wise?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur): a statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The acreage of land irrigated Distict-wise by Jamuna Canal and Bhakra Canals for the year 1969-70 is as below:-

Name of District	Western Jamuna Canal	Bhakra Canal System.
Ambala	8819	11974
Karnal	270633	399421
Hissar	410033	144+437
Jind	160548	317933
Mohindergarh	35224	Nil
Rohtak	545728	Nil
Gurgaon	Nil	Nil
Delhi State	41441	Nil
Total	1472426	2178765

श्री रणधीर सिंह: क्या सिंचाई मंत्री बताएंगे कि बैटरमेंट चार्जिज कब से लेना शुरू किया था और कब तक लिया जाएगा?

श्री रामधारी गौड़: बैठरमेंट चार्जिज के बारे में नहीं पूछा गया और न ही इस सवाल के जवाब से कोई ऐसा प्रश्न उठता है।

Nationalisation of Passenger and Road Transport in the State.

***1120. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Transport be pleased to state;

(a) the total number of road transport routes nationalised during 1970;

(b) the total number of road transport routes likely to be nationalised during the period from 1-1-1970 to 31-3-71 and during the period from 1-1-1971 to 31-3-1972;

(c) the period within which the passenger transport is likely to be completely nationalised in the State;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government for nationalising the goods transport if so, the details thereof; and

(e) the extra income that has been received by the Government during the year 1970 after nationalisation of road transport routes?

Transport Minister (Sh. Mahabir Singh):

(a) 102

(b) (i) 1-1-71 to 31-3-71 : 49

(ii) 1-4-71 to 31-3-72 : 125

(c) The passenger road transport is likely to be completely nationalised during teh year 1971-72.

(d) No.

(e) 53.25 lakhs.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहब के नोटिस में यह बात है कि पैसैंजर बेहद हैं और बसें कम हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है?

श्री महाबीर सिंह: इस बात का पूरा ख्याल है ओर हम कोशिश कर रहें हैं कि ज्यादा से ज्यादा बसें जल्दी से जल्दी चलाई जाएं। हमने फैसला किया है कि 1972 तक बसों के तमाम रूटस को नेशनेलाईज कर देंगे। जो नई बसें मिल रही हैं वे नये रूटस पर चल रही हैं। यही कारण है कि दूसरे रूटों पर कम बसें हैं। कुद अरसे के बाद ज्यों–ज्यों बसें ज्यादा होती जाएंगी लोगों की तकलीफ कम होती जाएगी। हमें पूरा ख्याल है कि पैसैजर्ज को तकलीफ न हो।

श्री दया कृष्ण: जींद डिस्ट्रिक्ट में जहां पेप्सू रोडवेज की बसें चलती हैं वहां बहुत दिक्कत है। न पेप्सू रोडवेज वाले बसें चलाते हैं और न ही हरियाणा गवर्नमेंट चलाती है। क्या गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी?

श्री महाबीर सिंह: इस सवाल का जवाब अगले क्वैश्चन में आयेगा उसी में जवाब देंगे।

चौ. लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लोकल बसें सिर्फ शहरों में ही चलेगी या गांवों में भी चलेगी?

श्री महाबीर सिंह: दरअसल बात यह है कि बसों की कमी है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम सारे रूटस

नेशनेलाईज कर रहे हैं। नेशनेलाईजेशन का काम जोरों से चल रहा है और नये रूटस पर भी बसें चला रहे हैं। इस काम के पूरा होने के बाद हम कोशिश करेंगे बसें ज्यादा हों और गांव वालों को सहूलियत मिल सके।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने देखा है कि लौंग रूल की जो बस हैं वे रास्ते के बीच में ही खड़ी हो जाती हैं। ये कन्डैम बसें हैं जिससे मुसाफरों को तकलीफ होती है। क्या मंत्री महोदय लम्बे रूटों पर नई बसें चलाने का विचार रखते हैं?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): मेम्बर साहब मेरे नोटिस में लाएं कि कौन सी खराब बस किस रूट पर चलती है। उसे फौरन रिप्लेस कर दिया जाएगा।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पेप्सू रोडवेज के साथ नेशनेलाइजेशन के बारे में गवर्नमेंट क्या समझौता कर रही है?

श्री महाबीर सिंह: यह क्वैश्चन आगे आ रहा है, तब जवाब दे देंगे।

चौ. लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्होंने बरवाला से देहली को बस चलाने का जो वायदा किया था, क्या वायदे के मुताबिक बस चलायेगे?

श्री महाबीर सिंह: यह सवाल मेरे जवाब से पैदा नहीं होता। मैं पूछ कर बताऊंगा।

चौ. जय सिंह राठी: क्या यह बात ठीक है कि जो नई बसें आती हैं उनमें से ज्यादा परसेन्टेज हिसार और गुड़गांव के डिपुओं की अलाट होती हैं और बाकी डिपुआों को पुरानी बसें अलाट होती है?

श्री महाबीर सिंह: मैं आनरेबल मेम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम रोड ट्रांसपोर्ट की नेशनेलाईजेशन कर रहे हैं उसी हिसाब से या रेशों से हम डिपुओं को बसें देते हैं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अगर आनरेबल मेम्बर किसी रूट या सर्विस का नाम बतायेंगे जहाँ खराब बसें चलती हैं तो ये उउसे इम्मिजियेटली चेंज करवा देंगे? जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ उसमें हमारा भी इंट्रैस्ट है और इनका भी इंट्रैस्ट है क्योंकि वह हिसार से सम्बन्ध रखती है। एक तो हिसार चंडीगढ़ वाया जीन्द बहुत ही थर्ड क्लास सर्विस चलती है। दूसरे जींद से चंडीगढ़ जो सर्विस है वह भी बहुत खराब है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर ने जिस रूटस के नाम बताये उनके बारे में मैं आज ही छानबीन करूंगा

और अगर वाक्या ही लम्बे रूटस की बसें खराब होंगी तो उन्हें फौरन रिप्लेस करेंगे।

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मानयोग मंत्री महोदय ने रूटस का नम्बर दिया है। ऐसा मालूम देता है कि नेशनेलाईज करने का जो अभी रूटस का नम्बर बाकी है वह काफी ज्यादा है लेकिन मेरे ख्याल में जितनी बसों को नेशनेलाईज कर लिया है। वे काफी ज्यादा होंगी। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि स्टेट कैरिअर्ज के कितने परमिटस नेशनेलाईजेशन के तहत आ चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, लगभग 82–83 परसेन्ट नेशनेलाईजड हैं मगर 17 परसेंट प्राईवेट आपरेटर्ज के पास हैं और ये भी मेरा ख्याल है 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे।

चौ. लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो सरकार ने पंचकुला के पास से हरियाणा एरिया में से बड़ी तेजी से सड़क निकाली है उसके ऊपर कब तक बस चलेगी?

श्री बंसी लाल: जैसे ही घग्गर का पुल तैयार हो जायेगा चालू हो जायेगी।

Surplus Land To Ejected Tenants

***1163 Shri Randhir Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:

(a) The number of rejected tenants, districtwise, to whom surplus land is to be allotted; and

(b) The number of applications lying pending for the said allotment?

राजस्व मंत्री (श्री नेकी राम):

(ए)	अम्बाला	13
	करनाल	19
	हिसार	32
	गुड़गांवा	67
	रोहतक	93
	महिंद्रगढ़	416
	जीन्द	640

(बी) 640 याचिकाएं।

श्री रणधीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह जितने मुजारों की लिस्ट दी गई है इसके अलावा जो एप्लीकेशनज आयेंगी उनकी भी सुनवाई की जाएगी?

श्री नेकी राम: अगर वे इम्क होंगी तो जरूर सुनवाई होगी।

श्री रणधीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि भिन्न–भिन्न जिलों में जो सरप्लस जमीन बाकी है वह कब तक अलौट कर दी जाएगी?

श्री नेकी राम: उसे भी जल्दी से जल्दी अलौट करने की कोशिश करेंगे।

श्री रणधीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कोई अवधि निश्चित है जब तक यह एप्लीकेशन समाप्त हो जायेंगी?

श्री नेकी राम: अभी यह कहना मुश्किल है।

श्री रणधीर सिंह: स्पीकर सहाब, डिस्ट्रिक्टस में भी 640 दरख्वास्तें पैन्डिग हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये कब से पैडिंग हैं?

श्री नेकी राम: इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब से आई हैं। (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह: स्पीकर साहब, जवाब क्योंकि ठीक आया नहीं इसलिए मैं दुबारा सवाल कर देता हूं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनके पास जो दरख्वास्ते पैडिंग हैं वे कौन से साल से पैडिंग है और कब तक इनकी डिसपोजल हो जाएगी?

श्री नेकी राम: पैंडिंग कब से हैं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बतला सकता लेकिन इनको डिसपोज औफ जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह दुरूस्त है कि ये 72–73 से पैंडिंग है?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): 72–73 तो अभी आया ही नहीं इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौ. जय सिंह राठी: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आखिरी दरख्वासत कौन सी तारीख और कौन से महीने में आई?

श्री नेकी राम: यह इन्फर्मेशन अवेलेबल नहीं है मगर इतना कहा जा सकता है कि जब से आई हैं तभी से पैडिंग हैं। (हंसी)

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय मेरे सवाल को समझ नहीं सके हैं इसलिए मैं दुबारा सवाल कर देता हूं।

श्री बंसी लाल: तारीख की डिटेल अवेलेबल नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो पैंडिग नम्बर है इसमें से कुछ दरख्वास्तें डिस्पोज औफ भी हुई?

श्री बंसी लाल: डिसपोज औफ होकर की बाकी 640 बची हैं।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मुझे यह सवाल भी और जवाब भी कुछ कट्राडिक्टरी मालूम देता है। सवाल में लिखा है कि

"(a) The number of rejected tenants, districwise, to whom surplus land is to be allotted; and

(b) The number of applications lying pending for the said allotment?"

तो मतलब दोनों का एक ही निकलतता है। जमीन, जो इजैक्टिव टेनेन्टस हैं उन्ही को एलोट होना है मगर पहले पार्ट के जवाब में उन इजैक्टिड टेनेन्टस का नम्बर जिनको जमीन एलौट होनी है 739 दिया गया है लेकिन दूसरे पार्ट के जवाब में कहा गया है कि एलौटमेंट के लिए 640 दरख्वास्तें पडिंग हैं। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि पहले इजैक्टिड टेनेन्टस कौन से हैं और दूसरे एप्लीकेशन्ज कौन सी पैडिंग हैं??

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब, जवाब एक ही है क्योंकि दोनों सवाल भी एक ही हैं।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मैंने टोटल लगा कर देखा है। पहले का नम्बर 739 आता है जबकि दूसरा नम्बर 640 है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास तो दोनों का नम्बर 640 है।

Shri Bansi Lal: In the Question, it has been asked:

"(a) the number of rejected tenants, districwise, to whom surplus land is to be allotted; and

(b) the number of applications lying pending for the said allotment?"

The same is the position in both the cases and the reply given is correct.

Mr. Speaker: It is a good question put by the hon. Member but the answer given is identical and there is no difference at all.

Shri Satya Narain Syngol: The Government have given answer to the first part of the question, which says;

"(a) the number of rejected tenants, districwise, to whom surplus land is to be allotted;".....

Mr. Speaker: Yes, they have given the break-up of the number.

श्री सत्यनारायण सिंगोल: मैं पूछना चहाता हूं कि जितने इजैक्टिड टेनेन्टस थे क्या उन सबकी एप्लीकेशन्ज पैडिंग हैं।

श्री बंसी लाल: जितनी एलौटमेंट होनी थीं वे होने के बाद इतनी एप्लीीकेशन्ज पैंडिंग हैं यह हमारा जवाब है।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, सवाल मैं इस बात को आगे क्वालिफाई कर रखा है कि जिनको जमीन मिलती हे। सारे टेनेन्टस कितने इलैक्ट हुए वह नहीं पूछा है।

In the reply, the number of ejected tenants, to whom surplus land is to be allotted, has been given, but it does not include the tenants who have been allotted the land. So, information is required on that point also.

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहब, कानून यह है कि इजैक्टेबल टेनेन्ट तभी इजैक्ट होता है जब उसको दूसरी जमीन एलाट होकर कब्जा मिल जाए। यह जवाब दुरूस्त मालूम नहीं देता। तो मैं इस बात की तशरीह चाहता हूं कि ये इजैक्टिव टेनेन्ट कैसे हो गए?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मेजिस्ट्रेट जो हुक्त लिखता है वह इस प्रकार होता है:

The tenant is ejected. But the actual possession will be taken when taken when the ejected tenant is accommodated on some other surplus land.

Shrimati Chandrawati: The Chief Minister's answer is quite confusing, Sir.

Chief Minister: Because the Hon. Member is alway****

Chudhri Chand Ram: Sir, there are two sets of.....

चौ. रणबीर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, यह तो कहा जा सकता है कि जवाब कन्फयूजड है लेकिन मेम्बर के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो राय दी है वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जाने चाहिए।

Shri Bansi Lal: My submission is that my replu was quite clear according to the law and according to the rules. Now if an hon. Member says that the Chief Minister's reply is confused one; when it quite clear, it means that there is confussion at one of the two places i.e. either the reply of the question given by me is not clear or there is ***with the hon. Member. So the ****is there with the hon. Member and that is not unparliamentary. (Interrputions)

चौ. रणबीर सिंह: यह कोई जरूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर या कोई मेम्बर कन्फयूजड हो, जवाब भी कन्फ्यूजड हो सकता है।

श्री बंसी लाल: जवाब कन्फ्यूजड नहीं है, आनरेबल मेम्बर **** में है।

चौ. रणबीर सिंह: जवाब में ही कन्फ्यूजन हो जाता है लेकिन मेम्बर **** नहीं हो सकता है।

Mr. Speaker: Anyway, the point is very clear. One hon. Member has said that the reply was confused one, and the answer to theat was that the hon. Member herself is confused. This is unparliamentary and I expunge it. (Thumping).

Shri Bansi Lal: No, Sir, My reply is quite clear and the hon. Member was herself****. The ruling of the Chair is there. But the Member herself was****. You can ask the House, there are no two opinions.

Mr. Speaker: Here is a list of kunparliamentary expressions and this expression is also there. "Confused" and "unintelligent" words are unparliamentary, when used with reference to an hon. Member.

Shri Bansi Lal: So, Sir her understanding was in****. The hon. Lady Member was not**** but her understanding was****

Shrimati Chandravati: Sir, the Chief Minister is using that word again. (Interruptions)

चौ. रणबीर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय आपके आदेश के बाद भी मुख्यमंत्री जी एक मेम्बर के बारे में उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। मै आपसे दरखास्त करूंगा कि ये बाद के शब्द भी सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जाये।

Mr.Speaker: They will be expunged. What I say, again the second time that particular word was not used.

Chief Minister: It was indirectly the same.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब हमारी स्टेट के अन्दर हो तरह के कानून लागू होते हैं एक तो पेप्सू का जो महेन्द्रगए और जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरे एरिया में करनाल रोहतक वगैरह में

पंजाब का ला लागू होता है। पंजाब ला के मुताबिक कोई भी इजैक्टिड टैनेन्ट इजैक्ट नहीं हो सकता जो स्माल लैन्ड ओनर है जब तक उसको दूसरी जगह जमीन न मिल जाये। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पेपर पर तो पोजैशन मिल गया, क्या मैं यह समझू कि फीजीकल पोजैशन दिए बगैर ही वे इजैक्टिड हो गये?

श्री बंसी लाल: मैंने यह नहीं कहा कि उनको पेपर पोजैशन तेा मिल गया है, लेनिक बाबू दया कृष्ण जी ने सवाल यह पूछा था कि मुजारे उस वक्त तक बेदखल नहीं किये जाते हैं जब तक दूसरी जमीन पर एकमोडेट नहीं कर दिए जाते। तो यह जो अप्लीकेशनज पडिंग हैं ये कैसे हैं और किस तरह से लोग इजैक्ट हो गए इस सवाल में कनफ्यूजन मालूम होता है। इसमें एमबिगिउटी दिखाई देती है उसके जवाब में मैंने कहा था कि अदालत डिग्री देती है। लिखती है कि टैनेन्ट इजैक्टिड कर दिया गया। But the actual possession from the tenant wil be taken only after he has been accommodated on some other surplus land. So, here the question is that they have been ejected on paper. The paper decree is there but the actual possession has to given to 640 persons.

चौ. चान्द राम: टैनेन्टस के अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखे जाय तो यह लगता है कि इजैक्टिड टेनेन्टस वे हैं जो आल रेड्डी इजैक्ट हो गए हों। जब वे अपीन जमीन बोते थे वरना इसके दूसरे माने नहीं निकाले जा सकते कि वह सिविल डिक्री या

पेपर डिक्री है या और है। इजैक्टीउ टेनेन्टस उसी वक्त लिस्ट में आता है जब पहले तो जमीन से बेदखत कर दिया हो। क्या हम यह समझें कि वह पहले जमीन से बेदखल कर दिया गया इन कम्पलाइन्स आफ डिग्री या यह समझें कि कब्जा नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट को कनफ्यूजन मालूम देता है तो सेक्रेट्री हैं, वे बड़े कानून के माहिर है उन्होंने भी जवाब को सुना है। वे इस सवाल का यह जवाब दे देते कि इस क्वैश्चन में कनफ्यूजन मालूम होता है।

Shri Bansi Lal: Sir, regarding interpretation of the Statute, I beg to dis-agree with the hon. Member.

विकास मंत्री (श्री सरूप सिंह): इजैक्टिड टैनेन्ट लफ्ज के माने हैं कि वे इजैक्टीड टैनेन्टस जिनके खिलाु आर्डर आफ इजैक्टमेंट पास हो गए उसके बाद वह अप्लाई करते हैं कि सरप्लस लैंड पर बैठने के लिए। जब तक उनको सरप्लस एरिया अलाट न हो जाये, वे दरखास्तें पैंडिग हैं लेकिन टैनेन्ट इजैक्ट हो गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ डिक्री इजैक्टमेंट की हो गई है।

Mr. Speaker: In any case, the situation appears to be satisfactory in the sense that even if a tenant may be ejected by an order but he will not be dispossessed or will not lose the land unless he is given some other land.

Chauhri Chand Ram: I wish in fact Advocate General be heard on this point in the House. There is a difference between the ejected tenant and ejectable tentant.

The ejected tenant are those who are to be ejected but have not actually been ejected.

Mr. Speaker: Question hour is now over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE UNDER RULES 45

Division of Road Transport Corporation.

***1121 Shri Daya Krishan:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the income that has accured to the Government from the Pepsu Road Transport Corporation during the financial years 1967-68, 1968-69, 1969-70, separately;

(b) whether the Government has taken any steps for claiming division of the assets and the liabilities of this Corporation; if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the non-division of the corporationis disdvantageous to the interest of Haryana State;

(d) if so; the period within which the division of this Corporation is likely to be completed;

(e) whether it is in the knowledge of the Government that the Pepsu Road Transport Corporation has removed its depot from Jind;

(f) if so, whether Government is considering any proposal to establish a depot of the Haryana Roadways at Jind;and

(g) if answer to pat (f) is in the affiemative the period whithin which depot is likely to start funanctioning?

Transport Minister (Shri Mahabir Singh):

(a) As final orders of Government of india on the scheme of division of Assets and Liabilities of the Corporation are stil to be passed, no income has been received by Haryana Government during the years 1967-68, 1698-69, 1969-70.

(b) Haryana Government have made persident efforts to get the division of Assets and Liabilites expedited. The matter stands referred to the Govt. of India for issuuing a directive regarding the Scheme of division.

(c) Yes.

(d) The Govt. of India have assured us that the final scheme of division will be notified very shortly.

(e) Pepsu Road Transport Corporation had only a sub-depot at Jind bu as per information supplied by General Manager, Pepsu Road Transport Corporation, Patiala, the same was damaged by fire during the Chandigarh agitation on 30-1-70 Since then, the control of its operation is being managed by Pepsu Road Transport Corporation, Patiala from its Sangrur and Patiala Depots.

(f) Government will decide about this matter after the division of the Pepsu Road Transport Corporation.

(g) As at (f) above.

Villages Having Girls High Schools

***1181. Sh. Randhir Singh**: Will the Minister for Education be pleased to state the total number of villages in Haryana having Government Girls High Schools together with the population separately of such villages?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Villages Having Government Girls High Schools in the State.

There are 45 Villages having Government Girls High Schools in the State.

Population of each village is given below in column No. 4.

Sr. No.	District		Name of the village	Population
1	Karnal			
		1	Fateh Pur.	4213
		2	Pathi	4019

			Kalyana.	
		3	Ismailabad	1119
2	Jind			
3	Mohindergarh			
		4	Bond	5206
		5	Imlota	2717
		6	Jawa	1396
		7	Jhojhu Kalan	3659
4	Hissar			
		8	Barwala	10723
		9	Chang	5904
		10	Rania	8535
		11	Saniana	3078
		12	Tosham	4392
5	Gurgaon			
		13	Gurgaon Village	8127
		14	Tigaon	5581

		15	Nagina	3271
		16	Hathin	4258
6	Ambala			
		17	Naraingarh	5685
		18	Mulana	2418
		19	Bilaspur	3174
		20	Shahzadpur	3454
7	Rohtak			
		21	Bhalaut	4030
		22	Farmana	4367
		23	Ismaila	7047
		24	Kalanaur	11840
		25	Rohna	4232
		26	Silana	2946
		27	Kirauli Pehladpur	2602
		28	Assauda	5600
		29	Chara	7541
		30	Dighal	8233

		31	Dubaldhan	6663
		32	Kossli	9808
		33	Nuna Majra	2745
		34	Badli	5931
		35	Nahra	2271
		36	Nahri	4438
		37	Sisana	5356
		38	Kharkhoda	6267
		39	Madina	2806
		40	Dulehra	3327
		41	Kansala	3420
		42	Bhainswal Kalan	5004
		43	Kahanaur	5690
		44	Sampla	3370
		45	Bainsi	4223

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Construction of Approach Roads

***1190 Ch. Ranbir Singh**: Will the Minister for Public Works be pleased to state:

(a) the names of approach roads sanctioned for the areas now comprising the state of Haryana as on 31.1066 together with the names of such roads sanctioned during the period from 1-11-1966 to 31-3-67;

(b) whether any ccontribution was received by the Government in the shape of free land, voluntary labour and cash for the roads, referred to in part (a) above; if so, details thereof together with the cost thereof in each case; and

(c) whether construction of any of the roads, referred to in part (a) above, has been completed; if so, details there of and if not, reasons therefor?

Public Works Minister (Sh. Ran Singh): (a) (b) & (c) A statement is land on the Table of the House.

STATEMENT 'A'

Statement showing the names of approach roads sanctioned far the area no comprising State of Haryana as on 31.10.66

Sr. No.	Name of road	Estimated Cost.	Contribution by villages			Progress of work	Remarks
			Land	Cash	Earth work (Voluntary labour)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GURGAON CIRCLE P.W.D. B&R BRANCH						
1	Constg. road from Sohna Tauru road to village Padeny.	36550	3608	2500		Work completed	
2	Nuh bus Stand to Nuh Byepass	22800	3030	1250		-do-	

3	Delhi alwar road mile 77 to Ferozepur Namak.	13000	1251	1250		-do-	
4	Delhi alwar road to village Hirmathala	9900	592	1250		-do-	
5	Delhi alwar road to village Mohamadpur Gujar Near Sohna Dhani.	25350	2295	2500		-do-	
6	Pataudi to Mumtazpur.	154000	15165	15000		-do-	
7	Manewar to Kasan.	151650	22530	20000		-do-	
8	Delhi Jaipur road to village Behrampur.	89600	9972	16000		-do-	
9	Approach road from Delhi Alwar road to village Salemba.	18900	1988	1875		-do-	
10	Bawal to Piranpura.	261900	33121	35800		-do-	

11	Maujawala Well to Railway Station.	39100	18000	2500		-do-	
12	Khera Dewat to Gurgaon Massani Road.	15400	11164	2500		-do-	
	ROHTAK CIRCLE P.W.D. B&R BRANCH						
1	R.J.R. to V.Madana Kalan.	55940	13146			-do-	
2	Rohtak Jind Road to Sunderpur.	30740	4800	3500		-do-	
3	Kalaur to Migana.	155000	54300			-do-	
4	rohtak Jajjar Road to vill. birdhana.	82330	21740			-do-	
5	rohtak Bhiwani road to Bhall Anandpur.	42660	19965	3000		-do-	
6	Madina Morkhra road.	167750	18000	38500		-do-	

7	Rohtak Bhiwani road in vill. Banyani.	76200	5557	10500	7550 (kankar)	-do-	
8	Lakhan Majra in Mandal.	90120	10882	7500		-do-	
9	Rohtak Jind road to Ghandi Bus Stand to Kharanthi.	79160	8979	6250		-do-	
10	Gohana Jind road to Vill. Nizampur.	68200	4442	10000		Work completed	
11	Rohtak Jind road to V. Bhagotipur.	27800	2100	5000		-do-	
12	Kharak Kalanga Road.	182000	157450	20000		-do-	
13	Chandi Bus Stand to V. Ghandi.	32280	2681	3750		-do-	
14	D.H.S. Road to Ballambha.	54500	8864	5000		Work in progress now. Previously work	

						was held up due to dispute in alignmend and the stay orders have been recently vacated by the Court.	
15	Circlular road to V. Sanari Kalan.	79450	7P.			Completed	
16	Samlla to Kultana road.	129400				-do-	
17	Sangi to Khidwali road.	93100				-do-	
18	S.K.R. road to V. Baliana.	88170	26440			-do-	
19	Bhalaut to Kiloi road.	168900	20010			-do-	
20	Rohtak Gohana road to Basantpur	13600	3980			-do-	

21	Gohana Lakhanmajra to Madina (Ahulana)	79000	6417			-do-	
22	Rohtak Gohana road to V. Makrauli Kalan.	85100	11395			Completed	
23	Bhalaut to Rukki (length 4.43 Kms.)	238000	50765			Only the leangth of 0.2 Kms. (one furlong) remains to be completed. The villagers are not prepared to hand over the land in this reach. It has been decided to acquire land in this reach and work will be	

						completed by December, 1971.	
24	D.H. Road to V. Baliana	141200	13230	14500		Completed.	
25	D.H. road to V. Chulana.	156500	17708	18000		There is dispute of alignment in last one K.M. reach which remains to be completed.	
26	Gohana Bhainswal to Gurukul Bhainswal.	52700	7660	10000		Completed	
27	Rurkhi to Chicharana (Length 4.30 Km)	241000	23730	18750		The consoliation of the road had since been completed but he tarring work	

						was not done as the villagers failed to deposit full amoutn of their share. In view of the recent instructions of the Haryana Govt. not to instist upon the share in cash where the land has been provided free of cost the surfacing has been in hand and shall be	

						completed soon.	
28	Madiana to Ajaib road.	198500	11785	27465		Completed	
29	Meham to Bhaini Surjan.	158400	20277	20000		-do-	
30	Bakhtawarpur App. road.	43000	3994	7500		-do-	
	MOHINDERGARH DISTRICT Share actually deposited Balance including cost of land Etc.						
31	Constg. app. road from Bachod to Pulana.	108700	37395			-do-	
32	Constg. an app. road from Lamba to Kasani.	79440	19890			-do-	
33	Constg. app. road from 6/6 of Dadri chuchhakwas road to V. Achina.	78100	12974			Only 1st phase was sanctioned which as since bbeen completed.	

34	Constg. App. road from mile 10/4 of Dadri Loharu road to V. Dudiwala.	217200	54300			4 K.M. completed collection of material in the balance reach is in progress, and the work is expected to be completed in year 1971.	
35	Constg. an app. road from mile 12 of D.M. road to V. Palri.	22180	4350			Work completed.	
36	Constg. an app. road from mile 9/2 of D.M. road to V. Changror.	45370	13452			-do-	
37	Constg. an app. road from mile 4/4 of D.M.	5700	3175			-do-	

	Loharu road to V. Kheri Butter..						
38	Constg. an app. road from Kalyana to Mandola.	51570	20587			-do-	
39	Constg. an app. road from mile 3 of Dadri Bhiwani road to V. Charkhi.	16100	8732			-do-	
40	Constg. an app. road Dadri Loharu Road to V. Mehra.	59640	14911			-do-	
41	Constg. an app. road from Dadri Loharu to v. Ladh.	40450	7999			-do-	
42	Constg. an app. road from mile 1 of dadri Chuchhakwas rod to V.	83950	20880	108		Work Completed	

	Dhani.						
43	Constg. an app. road to V. Mandola.	6940	3412			-do-	
44	-do- to V. Mandoli.	10660	4830			-do-	
45	Constg. an app. road from mile 6/4 of Dadri Loharu road to vill. bihri Kalan.	10200	5317			-do-	
46	Constg. an app. road from mile 11/6 of Dadri Bhiwani road to v. Nimriwali.	4220	1900			-do-	
47	Constg. an app. road from mile 5/6 of Dadri Bhiwani road to V. Pantawas Kalan.	23400	13860			Completed 0.48 K.M. out of 0.96 K.M. There has been dispute in alignment on	

						this road and is expected to be undertaken shortly after setting the dispute.	
48	Constg. an app. road from mile 10/6 of Dadri M. garh road to Jawa.	33240	8786			Completed.	
49	Constg. an app. road from mile 7/4 of Dadri Bhiwani road to V. Pantawas Kalan.	9400	4080			-do-	
50	Constg. an app. road from mile 10/6 of Dadri M. garh road to Bhandwa..	6770	2810			-do-	

51	Constg. an app. road from Manheru Rly. Station to V. Manheru.	37830	9744			-do-	
52	Constg. an app. road from Patuwas Rly. Station to V. Sanotkpura.	I/S	33900			-do-	
	(AMBALA CIRCLE P.W.D., B&R BRANCH)						
1	Village road from Allenby Lines to village Kaula in Ambala.	23300	4513	3600		Road Completed	
2	Village road from S.K. Road to Village Harnaul in Ambala.	144300	38707	32275		-do-	
3	Village rod from Ambala Cantt. to village Babyial via Mahesnagar.	71300	9840	2500		-do-	

4	-do- -do- via Water Works.	73000	15807	1500		-do-	
5	Village Road from Bahbalpur to Village Mohri.	183200	26620	30000		95% completed Land Acq. for 600 ft. is in dispute with land owners & the case is in process with land acquisition for final decision.	
6	Village Road from Ambala City to Village Nissambli.	220600	18200	35000		Road Completed.	
7	Village Road from Kalanpur Rly. Stattion to Kamalpur Tapu-1st Phase.	76000	3174	19400		-do-	

8	Village road from Ambala Cantt. to Village Boh.	53000	12675			-do-	
9	Village Road from Nilokheri Karsa dhand road to village Punjam.	63200	12938	2000		-do-	
	KARNAL CIRCLE P.W.D. B&R BRACN						
1	Constg. Bansa app. road	120500	30125	8540	Adjusted Competed in Col. 4		
2	Constg. from mile 68/8 of G.T. Road to vill. Uncha Samana	68000	17000	10000		-do-	
3	Constg. Garaunda Shickhupura road.	158845	29711	10711		Completed	
4	Constg. Garaunda to Kaimla Road.	105000	26222	20000		-do-	

5	Constg. Vill. app. road to Vill. Indri from Karnal Ramba Indri road.	10000	2500	1947		-do-	
6	Constg. Brass app. road.	67600	16900	18000		-do-	
7	Constg. Madlauda Mandi app. road.	29400	7350	Nil		-do-	
8	Constg. Link road from Pipli Pehowa Road to Thanesar Jansa Road.	78000	19500	Nil		-do-	
9	Constg. Constg. app. road to vill. Uplana.	96490	24120	2000		-do-	
10	Constg. Pujam app. road.	63200	15800	6070		-do-	
11	App. road panipat to Babail road	416200	97980	148950		Road metalled-surface painting completed 4.00 K.M.	

12	Panipat to Jatal Sutana Leheri road.	927200	82855	16325		Road metalled in full length. Surface painting completed in 3 K.M. Road will be completed during this year.	
13	Link orad Industrial area Panipat to Kabri.	167350	25013	4375		Road metalled including surface painting.	
14	App. road from mile 59/1 G.T. Road, to vill. Ganjbar.	44200	6375	45150	-do-	Road metalled including surface painting.	
15	App. road from mile 11 of	239400	14700	17475	-do-	Road metalled	

	Asandh road (Brgampur Bapnaut)					including surface painting.	
16	App. road from panipat Asanda road to Vill. Assan Kalan More Majra road.	1179600	46920	17475	-do-	Soling laid 18 K.M. Road metalled 6 K.M. Road will be completed during this year.	
17	App. road from mile 58/4 of G.T. road to village Barauli. 32.	45100	3621	7654	-do-	Road metaled and tarred.	
18	App. road from mile 45/8 of G.T. road to village Machrauli.	49570	4696	7701	-do-	Road metaled and tarred.	
19	App. road from mile 46/7 of G.T. road to village	118400	33845		-do-	Road metaled	

	Jatipur.					and tarred.	
20	App. road from mile 43/7 of G.T. road to village Manana.	118400	33845		-do-	Road metaled and tarred.	
21	App. road from mile 29/5 of Panipat Gohana road to village Burshau.	277200	46325	22975	-do-	Metalling completed Tarring first coat completed 4.5 K.M. Road will be completed during this year.	
22	Kheri Sharafall to Mandwal	135700	8540	2250 (4.2.69)	-do-	Road metalled.	
23	Constg. Bansa app. road.	120500	34125	8540		Completed.	

24	Constg. Brass app. road.	67600	16900	18000		-do-	

STATEMENT 'B'

Statement showing the names of app. roads sanctioned for the area now comprising State of Haryana from 1.11.66 to 31.3.67.

Sr. No.	Name of road	Estimated Cost.	Contribution by villages			Progress of work	Remarks
			Land	Cash	Earth work (Voluntary labour)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GURGAON CIRCLE P.W.D. B&R BRANCH						
1	Rewari Mohindergarh road to village Kharagwas.	29200	5564	2500		Work completed.	
2	Sohna Tauru Road to	23000	2303	1895		-do-	

	Village Sikarpur.						
3	Approach road from mile 12 of Hodal Nuh Pataudi Patuda Road (secion Kot to Nuh) to vill. Ujina.	18200	2153	600		-do-	
4	Godhana to Jiwara to Nurgarh via Palwas.	277000		30000		-do-	
5	Delhi Alwar Road to Badshapur to Teekli.	179700	16823	39000		-do-	
6	Nuh Palwal Road to Village Salaheri.	15320	1100	1250		-do-	
7	Constg. an approach road from Fazalpur to Janauli.	97830	13266	20000		-do-	
8	Constg. an approach	78250	71880			-do-	

	road from Geghera to Alika.						
9	Constg. an approach road from Nuh Palwal Road to village Badha (1st Phase)	9000	3210	1250		Work Completed	
10	Constg. an approach road from Nuh Palwal Road to village Gailpur.	10300	44440	2500		-do-	
11	Constg. an approach road from Khivi to Banswa.	54300	3550	10000		-do-	
12	Constg. an approach road from Delhi Mathra road to village Agwanpur.	20200	5750	2500		-do-	

13	Constg. an approach road from Delhi Mathra Road to village Mirapur.	18500	2225	1250		-do-	
14	Constg. an approach road from Palwal Sohna Rewari road to Village Tohrki.	6000	3647	2000		-do-	
15	Jhajjar Rewari road to village Gurwara (1st phase)	12790	704	1000		The villagers promised to give land free of cost and do the earth work voluntarily, but neither the earth work was done nor was	
16	Rewari Mohinder road to village Aulant (1st Phase)	18930	3591	2000			
17	Ghillar Bus Stand to Karwara Manakpur (1st Phase)	61300	10299	29000			

						the land transferred free of cost. As per latest policy of the Govt. these works will now be taken in hadn after the villagers – give land.	
18	Mile 12 of Hodel Nuh Pataudi road to Village Abdar (1st Phase)	21070	3481	1250			
19	Mauzabad to Rajpura via Dadawas (1st Phase)	69500	13389	39000			
20	Muzzafra Rerai to Village Shahpur Jat	6050					

	(1st Phase)						
21	Maujabad to Jaitpur (1st Phase)	18200	3823	9000		-do-	
22	Approach road from Jhajjar Subhana Road to Village Dhakla (1st Phase)	29800		6000		-do-	
	ROHTAK CIRCLE PWD B&R BRANCH **ROHTAK DISTRICT**						
1	S.K.K. Road to V. Paksma.	122000	28150	9000		Completed.	
2	-do- road to V. Assn.	29050	3553	3750		-do-	
3	Borin to Dubaldhan	165900		25000		-do-	
4	Purkies to Polangi Length 3.85 K.M.	269500	40750	12000		The work on this road	

						could not be started earlier as the beneficiaries did not deposit their share in full as per old policy of Government. As per revised policy of Government the beneficiaries have only to give land free of cost. The work has now been taken in	

						hand.	
5	Ranila Pilana Road (1st & 2nd Phase)	41350	9030	16500		Completed except surface.	
		58550					
6	Polangi to Jasrana Length 2.40 Km.	191600	22960	11000		As against Sr. No. 4.	
7	Beri Begpur (1st & 2nd Phase)	3200		2000		Completed.	
		21600					
8	Basant pur to vill. Dhamman	281700	28834	33270	64420	1st phase work was sanctioned in 3/67 and has been completed	

						except a length of 0.50 Km. which could not be completed on account of dispute in alignment 2nd phase work of this road has also been taken in hadn in view of the revised Policy of Government for having only free lnad from	

						beneficiaries.	
9	R.G.P. road to Chamarian 1st phase (length 2.86 Km.)	109700	12886	Nil	Nil	1st phase work was sanctioned in 2/67 could not be started as the beneficiaries did not deposti their shares in cash 10 inspite of numerous remainders. As per latest policy of Government beneficiaries	

						have only to give land free of cost No Land have so far been made available and as such work can't be taken in hand.	
10	Dhakala to Subana Jhajjar road (1st & IInd Road)	26900	4850	5000	7589	Completed.	
		44300				Completed.	
11	Dulehra to Goyala Kalan (1st, and 2nd phase)	85400	19027	17500			
		75040					

12	Sonepat Gohana road to vill. Lath.	59600	10630			-do-	
13	Somphla to Khasaranthi	651200	92200	60000		Work in this road remained held up due to dispute in alignment which has now been solved. Work is not in progress and will be completed by March. 72.	
14	G.T. Koad to Vill. Baga	295400	20212	60650		Work on this road is complete	

						where there is dispute in alignment. Land in these reaches will be acquired after Publication of land acquisition papers and work will be completed in these reaches after acquisition of Land.	
15	G.T. Road to V. Hasanpur	25000	650		7436	Completed.	

	MOHINDER GARH DISTRICT						
16	Constg. an app. road from V. Sanotkhpura to V. Makrani.	69000	14009			Completed.	
17	Constg. Kanina Kakrala app. road.	39490	26904			Completed. (Only 1st phase was sanctioned which has been completed)	
	AMBALA CIRCLE P.W.D. B&R BRANCH						
	Approach Roads-sanctioned from 1.11.66 to 31.3.1967.						
1	Village Road From G.T. Road mile 102 to Village Ram-Nagar in	62500	10889	12961		Road Completed	

	Karnal.						
2	-do- -do- 102/2 to Masana	33000	17642	11172		-do-	
3	Village Road from Harnaul to Darazpur.	112100	24703	11000		-do-	
4	Village Road from Mile 103/2 of G.T. Road to Chaurani Jattan in Ambala.	35400	14665	11250		-do-	
5	Village Road From G.T. Road to Village Madanpur-Lstph.	34490	15085	11750		-do-	
6	Village Road from Mile 2/8 of Nilokheri Karsa Road to village Ajanthli.	13525 79600		11420		The work for 1st ph. has since been completed and for the	

						2nd ph. revised Adm. Approval for Rs. 79600/- reveived vide C.E. No. 1121-B dt. 21.2.70. The work of metalling road nearing completion.	
7	Village Road from mile 4/6 of Nilokheri Karsa Road to Village Dabarthla.	40750 204300	38640			-do- -do- work nearing completion. revised Admn. approval for Rs. 204300/- recd. vide CE	

						No. 1133 9.2.70.	
8	Village Road from mile /13 of Thanesar Pehowa road to Village sandhouli.	18975 100600	26100			Completed. Revised Admn. approval received vide CE No. 957 dt. 9.2.70.	
	HISSAR CONSTRUCTION DIVISION						
1	ALAKHPUR TO Kheri Daulatpu	99160	4653	9598	13525	Completed upto 2.71 K.M.	
2	Dhana Khurd to Village Jatel	114850	38640	9698		Completed upto 3.00 K.M.	

3	Bhiwani Jind Road to Vill. Jatel.	58380	12227	4895	6466	Completed	
4	Hansi Jind road to Narnaund	28900	8593	4000	1980	do	
5	D.H.S. Road to Gill. Singla	89160	5248	7250	8258	Completed upto Wearing	
6	Ban to Barchharpur	436460	84800	64469		Completed.	
7	Mandhal Khurd to Village Bhaklema.	61270	3749	5000	5250	do	
8	Gulkani Milkhpur to Milapur.	13120	1093	5000	1370	do	
9	Dhani Amirpur approach. Road.	39390	9728			do	
10	D.H.S. Road to Dhani Piran	16350	2250		1931	Completed.	

11	D.H.S. Road to Dhani Kumarahan.	56080	18000			Completed upto 0.75 K.M.	
	SIRSA PROVINCIAL DIVISION						
12	Khuyana Malkana road	84230	10000		5432	Completed.	
13	Link Orad Nillanwali	51480	6220		1650	Completed.	
14	-do- Mattdadu	95050	14509		1378	Completed.	
15	-do- Kingra	60860	8326		5414	Completed.	
16	-do- Saktakhera	19930	2793			Completed.	
17	-do- Assakhera	86340	11903		3997	Completed.	
18	Approach road from Delhi Hissar Sulemanki road to vill. Gillakhera.	96700	18925			Completed.	
19	Approach road from Agroha Barwala road to	43650	3820	7478		Completed.	

	village Shamsukh.						
20	Approach road Adampur Siswal.	262000	60375			Completed.	
	KARNAL CIRCLE P.W.D. B&R BRANCH						
1	Samalkha Baheli raod	167000	64516	33625		Road metalled in full length including 1st cost of painting.	
2	Samalkha Naraina Road.	221700	85120	35000		Brick soling laid in full length Road mentalled first 3 K.M. Road could not be completed due to	

						dispute of alignment near village Dodpur.	
3	Gosian Khera to Shambho Kalan.	120100	Beneficiaries deposited their requisite share in full and all these roads have been completed. Details of beneficiaries share not readily available.				
4	Narwana Jind Road to Vill. Ghegrainl.	198000					
5	Narwana Jind road to Kasun, Khathar to Kasun)						
6	Balerkha an Bhupinder Sagar. Narwana road to Suraj Khera.						
7	Jind Rohtak road.Gobind Nagar.	28100					

8	Narwana Kaithal road mile 10/1 to Babi.	376100					
9	Jind to village Bibipur.	233450					
	KARNAL CIRCLE P.W.D. B&R BRANCH						
10	Constg. Taraori Sagga Road	446900	Free	40000		50% completed remaining length completed up to brick soling.	
11	Constg. Garaundha Arainpura Road	177600	do	18000		Completed	
12	Constg. Ranwar app. Road	162200	do	15600		do	

13	Constg. Beholi app. road.	327400	do	30625		do	
14	Constg. Kabri app. road.	167350	Free	Sugar Mill constribution Rs. 6 Lac for various Roads		Completed	
15	Constg. Begampur app. road.	281700	do	do		do	
16	Constg. Asan Morao Majri app. road.	614660	do	do		do	
17	Constg. Bareli app. road.	44200	do	do		do	
18	Constg. Bhari app. road.	390750	do	do		do	
19	Constg. Ganjbar app.	44200	do	do		do	

	road.						
20	Constg. Babail app. road.	23400	do	do		do	
21	Constg. Machauli app. road.	110000	do	do		do	
22	Constg. Jattipur app. road.	118400	do	do		do	
23	Constg. Manuna app. road.	118400	do	do		do	
24	Constg. Pudhshana app. road.	311450	do	do		do	
25	Constg. app. road to vill. Karora in Karnal Distt.	134000	do	do		do	
26	Constg. Sirsal app.	361400	do	Nil		do	

	road.						
27	Constg. Keorak app. road.	351000	do	5000		do	
28	Constg. Conder app. road.	159600	do	10000		do	
29	Constg. app. road to vill. Baragaon.	136800	do	13200		do	
30	Constg. Baragaon to Gheer app. road.	201250	do	5000		do	
31	Constg. app. road to village Tikri via Kailash.	132500	do	7100		do	
32	Babarpur Mandi app. road.	11200	do	1500		do	
33	Constg. Bhumshi app.	41250	Free	3000		Completed	

	road.						
34	Constg. Ajanttali app. road.	54100	do	5000		do	
35	Constg. Kamalpur app. road.	163100	do	22000		do	
36	Constg. Faridpur app. road.	68860	do	8000		do	
37	Pehowa Kaithal road to vill. Keorak	35100	6026			Road metalled.	
38	Asandh Rajaund road to Village Rihera (approved 1st Phase only)	186600	13000			The villagers have neither done earth work upto 1969 and nor they deposited their share in	

						Cash. Now on revised pattern of village roads the work has been taken in hand. Earth work completed B&C 80% completed. Soling and supply of stone metal is in progress.	
39	Constg. Ranwar app. road.	162200	40550	15000		Completed.	
40	Constg. app. road to vill. Karora in Karnal	134600	33650	8000		do	

	District.						
41	Constg. Sirsal app. road.	361400	90350	Nil		do	
42	Constg. Gonder app. road.	159600	39900	10000		Out of the total length of 3.7 K.M. One K.M. completed.	
43	Constg. app. road to village Baragaon.	136800	34200	13200		Completed	

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी चौड़ी स्टेटमैंट तो इस वक्त सदन के सामने लाना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ रोडज इसमें जरूर रह गई हैं, जो इसके अन्दर शामिल नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष: सांधी, खडवाली तो शामिल कर दी हैं।

चौ. रणबीर सिंह: सांधी से खडवाली तक की शामिल कर दी हैं लेकिन सांधी की रोड शामिल नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दो सप्लीमेंट्री मैं कहना चाहूंगा। जहां तक चमरिया का ताल्लुक है मंत्री महोदय ने कहा उस गांव में कोई काम शुरू नहीं हुआं वहां तो अर्थ वर्क का काम शुरू हो गया है। उसके बारे में कहते हैं कि जमीन नहीं मिली है मैं बताना चाहता हूं कि उनका यह जववाब सही है?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Mr. Speaker, the Hon. Member says that there is a road about which in the statement it has bene stated that the work has been started so far while the earth work is complete. I may clarify this point. Mr. Speaker, we have to complete all the roads within 2½ years or in two years and three months. So keeping in view the emergency of going ahead with this work of connecting every village with road in the State, some times, even the local authorities have been authorised to go ahead with the construction work wherever the land is available. Since, it was a short notice question. it is possible that complete information may nkot have reached the Headquaters. However,

if the Hon. Member says that the earth work has been done. it is still better.

चौ. रणबीर सिंह: यह मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वह एक हालात को देखते हुए ठीक जवाब दिया है लेकिन इसमें जो प्रश्न उठाया है वह इसलिए उठाया है कि वहां पर जमीन कैसे नहीं मिली जिसकी वजह से काम नहीं हो सका। अर्थ वर्क हुआ है वह गलती हो सकती है कि टाईम थोड़ा था, इसलिए एक दो बातें मैं मुख्य मंत्री जी को बाद में लिखवा दूंगा।

Sh. Bansi Lal: They will be fully considered.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, अगर वह चमारियां का काम नहीं करेंगे तो किस का करेंगे?

चौ. रणबीर सिंह: यह तो महामंत्री जी कह दे, मैं नहीं कह सकता।

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker: Call Attention Motion No. 4 given notice of by Ch. Ranbir Singh, M.L.A. regarding the imposition of a cut of 30% in the supply of electricity to the sugarcane crushers on the basis of electricity consumed by them during the months of October and Novermber, 1970, and thereby harming the interests of sugarcane growers and the industry is admitted. The Hon. Member may please read his motion.

Ch. Ranbir Singh: Sir, I beg to draw the attention of the House to this urgent matter of public importance that the Haryana State Electricity board has taken a decision to impose a cut of 30 per cent in electric supply on the electricity consumed by sugarcane crushers in the State during the months of October and November, 1970.

The crushing season had hardly started from the gag end of November and they had hardly consumed and electricity during these two months. Therefore, to apply cut on the basis of electricity consumed by them during October and November, 1970, is quite wrong and it would ruin the industry and also harm the interests of sugarcane growers in the State.

As the matter is of urgent public importance, hence this Call Attention Motion.

Mr. Speaker: The Minister for Irrigation and Power may kinldy make a statement.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री रामधारी गौड़): बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि इतनी जल्दी जवाब तैयार नहीं हो सकता।

Mr. Speaker: You can do it later.

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, अगर दोपहर तक जवाब तैयार हो गया तो भी उसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट शाम को डिसकस होनी है।

श्री अध्यक्ष: उस वक्त शायद आप कुछ बता सकें।

श्री बंसी लाल: जब वह रिपोर्ट आज डिसकशन के लिए रख दी गई हैं और जब डिमांडज और ऐप्रोप्रिएशन बिल आदि सब चीजें यहां आ गई हैं तो यह मोशन ऐडमिट नहीं होनी चाहिए थी। अब चूंकि चेयरम की रूलिंग आ गई है इसलिए I cannot say anything. But, this motion should not have been admitted in view of these three things.

Mr. Speaker: It is a minor matter .....

Sh. Bansi Lal: If it is a minor matter then it should not have been admitted at all.

Mr. Speaker: It is a simple question .....

Sh. Bansi Lal: It may be simple. But, here the point is that we are going to discuss the Demands for grants right now and then the Appropriation Bill in respect of these Demands and the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board in the afternoow sitting. So, the Hon. Member has a right to say whatever he wants to and he can do so during the discussion on the Demands for Grants, the Appropriation Bill and the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board and this motion should be dropped.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि शूगरकेन के सिलसिले में डा. रामेश्वर दास जी का एक प्रश्न था। मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी ने यह बड़े जोर से ऐलान किया था कि जहां फैक्ट्रियां हैं वहां पर भी हमने शूगरकेस क्रशर चलाने की इजाजत दी है तो इसके ग्रोवर को कोई नुकसान नहीं

पहुचेगा। अगर बिजली बन्द कर दी गई तो यह इजाजत कागजी ही रह जाती है, क्योंकि यह क्रशर बिजली से चलते हैं। तो सवाल तो मामूली सी बात का है। यह ठीक है कि सइ वक्त ये कुछ न कहना चाहते हों लेकिन जिस वक्त बजट यहां आए उस वक्त मैं उम्मीद करता हूं कि शायद स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के ऊपर कोई न कोई बहस हो सकेगी। तो कया उस वक्त ये जवाब देंगे?

श्री बंसी लाल: जवाब देने की कोई बात होगी तो जवाब यिदा जाएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा।

Mr. Speaker: What I would like to clarify is that it is a definite matter as a result of which certain sections, small or a lettle bigger, having genuine grievances, would suffer or were going under loss. And, through this motion, the hon. Member only tried to divert the attention of the Minister concerned so that they may get reasonable relief.

Sh. Bansi Lal: I would again like to submit that when the Demands for Grants are coming up for discussion right now there was no idea of this Call Attention Motion. Every thing regarding public interest could have been very well brought during that discussion. And, then the Appropriation Bill is coming up and also there is specific item for the consideration of the Report on the Electricity Board. Every thing of public interest could be siad during these discusssiions and there was no idea of admitting this motion at all.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले निवेदन किया यह प्रश्न खाली इनका नहीं है जो शुगरकेस क्रशर चलाते हैं। इस सदन को आश्वासन दिया गया था जिस वक्त इस बात का जिक्र आया था कि इतना बौंडिड शुगरकेस फालतू हो गया है। यह फालतू शुगरकेन ऐसा है जिसको फैक्ट्रियां क्रश नहीं कर सकतीं। उस वक्त मंत्री महोदय ने बताया था और मुख्यमंत्री जी ने उसकी ताईद की थी कि हमने जहां कारखाने या शुगर मिल लगाए हुए हैं उस एरिये के अन्दर शुगरकेन क्रश करने की इजाजत दे दी है ताकि गन्ना जो बच गया उसको किसान पीड़ सकें। मेरा कहने का मशा यह है कि यह जो इजाजत दी है वह कागजी बन जाती है और जो काफी तादाद में गन्ने की काश्त कर रहे हैं अगर वे अपना गन्ना पिलवा न सके तो उनको इससे काफी नुकसान होगा।

Sh. Bansi Lal: We cannot go by the presumption of the hon. Member and cannot, therefore, give any definite answer.

Ch. Ranbir Singh: Mr. Speaker, I am on my legs. Unless he rises on a point or order, I have a right to have my say.

Mr. Speaker: We have heard. Your thing is clear. A decision has already been given.

Sh. Bansi Lal: I am sorry, the Government is unable to reply to this Notice. The policy of the Government has been made clear time and again and even the hon. Member

has said that the Government has given an assurance on the floor of the House. If the Government has already given an assurance, there is no necessity of discussion. I am sorry, the Government is unable to give a reply to this necessary Call Attention Notice.

Mr. Speaker: I also remember that the Hon. Member of Agriculture has very clearly stated that so much sugarcane is lying that the mills may not be able to crush. Therefore, they had, as a special case, authorised the farmers to start their own crushers.

Sh. Bansi Lal: What else they now want. There is nothing more we can do. I am very clear about it.

Mr. Speaker: He feels that this cut of 30% may affect the farmers.

Sh. Bansi Lal: Whoever is living in the state will be affected by the cut. It is very simple.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, आन प्वाइंट आफ आर्डर, मेरी एक सबमिशन है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 परसेंट कट वाली शूगरकेन ग्रोअर्ज की बात बिल्कुल पब्लिक इम्पारटैंस की बात नहीं है जबकि उससे हजारों शूगरकेन ग्रोअर्ज अफैक्ट होते हैं। मैं क्या इनसे जान सकती हूं कि फिर पब्लिक इम्पारटैंस की कौन सी बात है जो हम यहां कहें?

श्री बंसी लाल: स्पीकर सहाब, ये तो भाषण करने लग गयीं। भाषण तो जब इलैक्शन टूर पर जायेंगी तो हमारे खिलाफ

करेंगी ही। Therefore, kindly ask her what is her point of order?

Smt. Chandravati: It is not for you. It is for the Chair to aks whether I am on point of order or not. (Interruption)

Mr. Speaker: Let ut hear her point of order. She has also a right to put her point of view.

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस चीज से बहुत सारे लोग अफैक्ट होते हैं और इससे ज्यादा मैं कोई पब्लिक इम्पारटेंस की बात नहीं सकझती इसलिए गवर्नमेंट को इस बारे में कोई एश्योरेंस देना चाहिए .....

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमान शारदा रानी कुंवर): सर, क्या प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े होकर सबमिशन पेश की जा सकती है?

Sh. Bansi Lal: I want to point out that there is no cut imposed on sugrcane crushers. (Interruptions)

Mr. Speaker: If that is so then the whole thing is clear. (Interruptions)

Sh. Bansi Lal: Mr. Speaker, Sir, my first point is that there was no need of admitting such call attention notice when the Government had already given an assurance. The second thing is that we are going to discuss the Demands for Grants right not and then in the afternoow session, the Appropriation Bill and in the end of the session today we are

going to take up the report of the Electricity Board. So there is no need of this call attention notice at all.

Mr. Speaker: I think let us keep our tempers cool. The main thing is that there is no need.

Sh. Bansi Lal: Even if there is any, my submission is that the admission of this call attention notice is against the parliamentary conventions in the country.

Mr. Speaker: We have examined our rules. We are prepared to examine it again.

Sh. Bansi Lal: Ruling is there. But my protest is that it is wrong admission. But the ruling, is ruling. Under these circumstances no such call attention motion should have been admitted.

(Many Honourable Members rose to speak.)

Mr. Speaker: You are going out of control. Now you have heard the Leader of the House. I personally feel that if there is no cut on the crusher then there is no much need for this call attention motion. There is no point to argue it further.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपसे, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और सदन से माफी मांग सकता हूं यदि इन्होंने पहले जो कट का सरकुलर इशु किया हुआ है, उसके बाद कोई दूसरा सरकुलर इशु करके उसको रैस्टोर किया हो और कहा हो कि यह कट न लगाया जाये क्योंकि यदि ऐसा हुआ हे तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह कालअटैन्शन–मोशन जो मैंने कट

का इस सदन में लाया है, यह न केवल काश्तकार यानी केन ग्रोअर के हक में ही है बल्कि गवर्नमेंट के भी हक में हैं तोकि इनकी सही बात को लोगौं तक पहुंचाया जा सके।

Sh. Bansi Lal: He can bring this during the discussion on the Demands for Grants and the Report of the Electricity Board .....

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जितनी बातों पर यहाँ बहस की जाती है उनमें से हरेक का जवाब नहीं दिया जा सकता। न तो आज तक कोई सरकार जवाब दे सकी है और न ही दे सकेगी। एक खास प्रश्न का खास ही जवाब हो सकता है, जैसा अभी बताया गया है। मुझे तो खुशी है और यह जाहिर हो गया है कि इन्होंने कट न लगाने के लिये सरकुलर इशु किया है। इसलिए अब मैं सदन से माफी चाहूँगा क्योंकि मैंने सदन का काफी समय खराब किया। मैं चाहूंगा कि यदि इन्होंने सरकुलर इशु किया है तो इन्हें साफ तौर पर मानना चाहिए कि हमने ऐसा किया है।

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब बात यह है। Now we have talked enough on this point. The Leader of the House is not questioning the ruling. What he is saying is, in fact as a matter of protest, that in his his view it was not a matter of public importance. What I have said is, in case there is no cut, I may not agree with you. So let us close it here. We have discussed it enough. The purpose has been achieved.

DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker: According to the previous practice all the following Demands will be deemed to have been read and moved:

That a sum not exceeding Rs. 27181570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 19-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 50861690 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 31-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 2056000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 95-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

That a sum not exceeding Rs. 11710300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 35. Industries.

That a sum not exceeding Rs. 28351000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

That a sum not exceeding Rs. 40537310 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 42-Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 45143850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) (44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)

That a sum not exceeding Rs. 24519750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head Charges on Irrigation Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 53000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 119130190 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

That a sum not exceeding Rs. 45964840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 50-Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 17430600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head charges on Building and Roads Establishment.

That a sum not exceeding Rs. 3212580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 52-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 221604000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 103-Capital Outlay on Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 11018940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 9-Land Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 925900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 10-State Excise Duties.

That a sum not exceeding Rs. 678400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 11-Taxes on Vehicles.

That a sum not exceeding Rs. 3447490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 12-Sales Tax.

That a sum not exceeding Rs. 2221900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 13-Other Taxes and Duties.

That a sum not exceeding Rs. 391260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 14-Stamps.

That a sum not exceeding Rs. 51580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 15-Registration Fees.

That a sum not exceeding Rs. 2422900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 18- Parliament State/Union Territory.

That a sum not exceeding Rs. 4881010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 21-Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs. 4828170 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 22-Jails.

That a sum not exceeding Rs. 45745280 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 23-Police.

That a sum not exceeding Rs. 455970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 25-Supplies and Disposals.

That a sum not exceeding Rs. 2371860 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 26-Miscellaneous Departments.

That a sum not exceeding Rs. 56700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 27-Scientific Department.

That a sum not exceeding Rs. 202521040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 28- Education.

That a sum not exceeding Rs. 43934300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 29-Medical.

That a sum not exceeding Rs. 62719100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 30-Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 19666830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 33-Animal Husbandary.

That a sum not exceeding Rs. 8436400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 34-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 15989870 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs. 14257490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 38-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 11650440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 39-Miscellaneous, Social and Development Organisations.

That a sum not exceeding Rs. 101799350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 57-Roads and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 23000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 64-Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs. 12503500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 65-Pension and other Retirement Benefits.

That a sum not exceeding Rs. 37600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 67-Privy Purses and Allowances of Indian Rules.

That a sum not exceeding Rs. 8170850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 68-Stationery and Printing.

That a sum not exceeding Rs. 10408090 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 70-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 44320570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 71-Miscellaneous.

That a sum not exceeding Rs. 57250 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 76-Other Miscellaneous compensations and Assignments.

That a sum not exceeding Rs. 999500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 109-Capital Outlay on Road and water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 20844140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 290000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 120-Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs. 513038710 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head 124-Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

That a sum not exceeding Rs. 191115300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the

charges unber head Loans to Local Funds-Private Parties, Loans to Government Servants.

That a sum not exceeding Rs. 10517280 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges unber head Inter-State Settlement.

A member while speaking will please indicate the Demand on which he is raising discussion. After applying guillotine I will put the Demands, one by one, to the vote of the House.

(Ch. Chand Ram rose to speak .....)

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): स्पीकर साहब, कया आप बतायेंगे कि आप गिलोटिन कब एप्लाई करेंगे ताकि हमें कुछ अन्दाजा हो जाए?

श्री अध्यक्ष: साढे बारह बजे। आप जितना समय चाहेंगी उतना टाईम आपको मिल जायेगा।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: मुझे तो 45 मिनट चाहिएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, दे देंगे।

चौ. चाँद राम: स्पीकर साहब, मुझे बोलने का कितना समय मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: बारह बजे तक।

महन्त गंगा सागर: स्पीकर साहब, थोड़ा सा टाईम मुझे भी चाहिए।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मैं तो सारे सैशन में बोला ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया है .....

मुख्य मंत्री: (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, हम अपनी पार्टी के स्पीकर्ज की लिस्ट पाँच मिनट में दे देंगे।

Mr. Speaker: I am afraid if there are five members from this side and five from that side, then you will get only seven minutes each. Some of you can speak in the evening.

महन्त गंगा सागर: स्पीकर साहब, मैंने तो न ही गवर्नर ऐड्रेस पर बोला है और न ही बजट पर बोला है।

श्री अध्यक्ष: टाईम तो था, आप बोल लेते .....

महन्त गंगा सागर: मुझे किसी ने टाईम ही नहीं दिया। .....(विघ्न)

Mr. Speaker: I suggest that two members from each side may speak. It is upto you to decide it.

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, अगर आप किसी को भी 5 मिनट ज्यादा न दें, तो 15 मैम्बर बोल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह तो आपकी सजैशन है और इट इज अप टू यू।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, यह तो हमारे मुकाबले में वन–थर्ड भी नहीं है। जनता तो इनको पूछती ही नहीं। आपको टाईम मैम्बरों की गिनती के हिसाब से देना चाहिए। आप आधा इनको कैसे देंगे?

श्रीमती शकुन्तला: हमारे मैम्बर तो आधा–आधा घन्टा बोलना चाहते हैं।

श्री बंसी लाल: इन्हें बाहर खड़ी कर दो, बोलती रहेंगी .....।

श्रीमती शकुन्तला: स्पीकर साहब, हम बाहर खड़े होकर बोलने के लिए यहां नहीं आये, हम तो यहां हाउस में बोलने के लिये हैं।

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, फाइनस मिनिस्टर साहिबा 45 मिनट मांगती हैं। इनके इस टाईम को कुछ कम कर दिया जाए ताकि उसमें से कुछ हमें मिल जाए।

Mr. Speaker: I would suggest that the Opposition may take half an hour and the treasury benches 45 minutes.Teh Finance Minister may also reduce her time accordingly.

Sh. Bansi Lal: I have also to intervene at some stage.

Mr. Speaker: You can intervene in between.

Sh. Bansi Lal: I have to take my own time for intervening. (Interruptions)

Mr. Speaker: What we will do if the house likes ..... (Interruptions)

No interruptions please. When I am speaking, I do not want any body to interrupt uncessarily. Since there are still so may Members who wish to speak, I suggest that we may extend the time of this sitting by half an hour.

Sh. Bansi Lal: No, please.

श्री अध्यक्ष: शाम का एप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है, मैम्बर उस समय बोल सकते हैं। हाउस इस पर फैसला कर ले।

Sh. Bansi Lal: The Appropriation Bill is coming up in the afternoon sitting. It has to be passed and then sent to the Government for his assent. We cannot, therefore, extend the time of this sitting.

Mr. Speaker: Alright, I give half and hour to the Opposition and and 45 mimutes to the Treasury Benches. I would also request the Finance Minister to reduce her time.

चौ. चाँद राम: मैंने अभीतक कुछ नहीं बोला इसलिए मुझे बोलने दिया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौ. चांदराम आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

चौ. चाँद राम: मैं नहीं बोलना चाहता।

Mr. Speaker: Ch. Chand Ram, you appear to be annoyed. You stood up first and then sat down.

Ch. Chand Ram: No, I am not annoyed.

Sh. Bansi Lal: Ch. Chand Ram should be given time. He has not spoken since the start of the session.

Mr. Speaker: Half an hour for the Opposition. Two Members can speak from their side.

चौ. चाँद राम: स्पीकर साहब, मैं इस बात पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि यहां पर एक–एक मैम्बर दो–दो, तीन–तीन बार बोल चुके हैं और मैं एक दफा भी नहीं बोला। मेरा भी कुछ राइट है या नहीं?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, चौ. चांद राम को बोलने का मौका जरूर दिया जाए दूसरे मैम्बर यहां पर छे–छे बार बोल चुके हैं।

Mr. Speaker: We are losing a lot of time to this.

श्री रणधीर सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि चौ. चांद राम कौन सी तरफ से बोल रहे हैं?

Mr. Speaker: Let us not waste any more time we have had enough of discussion on this.

महन्त गंगा सागर: स्पीकर साहब, आधा घंटा आपने दिया। इसमें से अगर चार बोलें तो साढ़े–सात मिनट हरेक के

हिस्से में आते हैं। ऐसा किया जाए कि दस मिनट चौ. चांदराम ले लें और बाकी पांच–पांच मिनट ले लें। (विघ्न)

Mr. Speaker: No interruptions, please. I expect you, Mr. Vij, not to interfere. Ch. Dal Singh has just spoken. Another member has also taken his time from this side. So, new let Ch. Chand Ram start. He may take 15 minutes, if a few others also want to speak from this side, let them take 4/5 minutes each.

चौ. चाँद राम: स्पीकर साहब कुछ बात बजट पर कहने से पहले में अपनी पोलिटिकल पोजिशन को इस सदन के द्वारा जाहिर करना चाहता हूँ।

चौ. दल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, स्पीकर साहब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई आनरेबल मैम्बर अपनी पोलिटिकल पोजिशन के बारे में सदन में बोलकर सदन का टाईम खराब कर सकता है? (व्यवधान)

Mr. Speaker: No interruptions, please. It appears that the Members are tired. Demands have been read and moved. A Member while speaking has to indicate the demands on which he wishes to raise a discussion. So, I think that the Hon. Member cannot explain his political position at this stage.

चौ. चाँद राम: स्पीकर साहब, फिर मैं बोलता ही नहीं।

श्री रणधीर सिंह: अध्यक्ष महोदय जनसंघ पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं बोला है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: स्पीकर साहब, चौ. साहब बहुत सीनियर मैम्बर हैं एक–दो मिनट जो कुछ यह बोलना चाहें इन्हें बोलने दिया जाए।

Mr. Speaker: A Point of Order has been raised and I have to go by certain Rules and Procedure. I have given 15 minutes to Ch. Chand Ram Ram to speak.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: अगर कोई बात होती है तो वह हाउस में ही बोलने की होती है (विघ्न)

Mr. Speaker: Well. we have to go by certain Rules and Procedure. A Point of Order has been raised. Today, there is discussion and voting on Demands. But, in case some statements have been made againt the Hon. Member casting reflections, then he can ask for time for giving personal explanation. However, while speaking on Demands, he cannot speak on other such things. So, let him first speak on personal explanation, if he wants to, and then speak on Demands.

चौ. चाँद राम: मैं बहुत पुराना मैम्बर हूँ। जो कुछ मेरे खिलाफ कहा गया है उसके खिलाफ मैं प्रोटैस्ट करता हूं। कोई भी मैम्बर खड़ा होकर यहां जो कुछ उसके मन में आए कहने लग जाता है। क्या वह ऐसा कर सकता हे? इसके बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः चौ. चांद राम आप यह बताएं कि किस मैम्बर ने आपकी पोजिशन खराब की है?

चौ. चाँद रामः स्पीकर साहब, कोई भरी मैम्बर यहां खड़ा होकर जो मन में आए कहने लग जाता है।

श्री अध्यक्षः चौ. साहब अगर आप पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिए कुछ टाईम चाहते हैं तो आप साफ कहें उसमें कुछ मुश्किल नहीं है।

श्री दया कृष्णः आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। स्पीकर साहब, एक आनरेबल मैम्बर ने चौ. चांद राम जी के बारे में कुछ कहा था जब वे स्पीच करने के लिए खड़े हुए थे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर उस तरीक से इनको एतराज है तो यह पहले पर्सनल एक्सप्लेनेशन देकर बात में अपनी स्पीच दे सकते हैं।

11.00 A.M.

Mr. Speaker: A very clear Ruling has been given and I see not reason why the Hon. Member should insist. I have said we will give him time for personal explanation and thereafter he can continue to speak on demands.

Smt. Om Prabha Jain: Ch. Sahib (Ch. Chand Ram) we will be benefited by your address. Pleased speak.

चौ. चांद राम (बबैन.एस.सी.): स्पीकर साहब, यह जो बजट हमारे सामने है यह मैंने खासा गौर से पढ़ा है और इसमें

कोई शक नहीं कि यह बजट जो है यह एक प्रोग्रैसिव बजट है और इसको एक पहरे से दूसरे पहरे तक जब हम पढ़ते हैं (विघ्न)

Mr. Speaker: Kindly do not mix up two things. I have said that one is 'personal explanation' and the other is your speech on Demands. So, you please speak on one and then start with the other.

चौ. चांद राम: मैं समझ गया हूँ स्पीकर साहब, चूंकि आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते इसलिए मैं बोलता ही नहीं।

श्रीमती शकुन्तला (साल्हावास, एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को बड़े ध्यान से पढ़ा है। चौ. चान्द राम जी ने और उनके पहले कई और ट्रैजरी बैचिज वाले मैम्बरों ने कहा है कि यह बजट बड़ा ही सराहनीय है लेकिन मेरे अन्दाजें से यह केवल कागजों पर ही अच्छा है। (इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुई)। अगर हम इस बजट को लेकर जनता के सामने जायें और लोगौं की राय पूछें तो मेरे ख्याल में सब यही कहेंगे कि यह सिर्फ कागजी घोड़ा है। तो मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा आपकी मारफत निवेदन करूंगी कि इस बजट के अन्दर जो आंकड़े हैं वह आधे से ज्यादा गलत साबत हुए हैं। सबसे पहले मैं एग्रीक्लचर के मुतालिक बताना चाहती हूँ। वित्त मंत्री साहिबा ने खेती के बारे में बताया है कि इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है और हरियाणा का नाम दूसरी स्टेटों के मुकाबले में दूसरे तीसरे नम्बर पर आता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं यह बताना चाहती हूं कि किसान लोगों ने

मेहनत की है, वह मेहनती होते हैं, अपना पेट और देश के लोगों का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद वे यह देखते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की है उसका उनको क्या फायदा पहुँचा है? अगर उनको फायदा नह दिखाई दे तो वे आगे के लिए उम्मीदे छोड़ बैठते हैं और अगर उनको फायदा दिखाई दे तो वे और भी ज्यादा मेहनत करते हैं इस बजट में कहा गया है कि आने वाले साल में इससे भी ज्यादा प्रोग्रेस होगी लेकिन जब तक किसानों को उनकी पैदावार का पूरा फायदा नहीं पहुँचाया जाएगा वे मेरे ख्याल में अपनी हिम्मत तोड़ बैठेगे और जितना वे अब मेहनत करने के लिए उत्सुक हैं आगे के लिए वे उतनी मेहनत नहीं करेंगे। वित्त मंत्री साहिबा ने बताया है कि पहले से ज्यादा गन्ने की उपज हुई है। मैं मानती हूं कि हुई है। किसानों ने मेहनत की है और ज्यादा गन्ना पैदा किया है उसकी वजह यह है पहले वाली जो सरकार थी उन्होंने किसान को गन्ने की कीमत पूरी दिलाई थी और उससे उनका हौसला बढ़ा था लेकिन जो मौजूदा सरकार है इसने उनका गन्ना सात–आठ रूपए क्विन्टल के हिसाब से बिकवाया है जबकि तूडा भी उससे महंगा बिकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा जब गन्ना तूड़े से भी सस्ता बिके तो फिर किसान का उत्साह कैसे बना रह सकता है? मैंने अपनी आँखें से देखा था किसानों ने अपने गन्ने के खड़े खेतों को आग लगा–लगा कर जलाया था क्योंकि वह जब गन्ने को काट कर मील में ले जाते थे। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): वह कब लगाई थी बहन जी?

श्रीमती शकुन्तला: वह पिछले साल लगाई थी और इसके बोर में मैंने तब भी सवाल किया था, लोगों का तब बहुत नुकसान हुआ था। मैं निवेदन करूंगी कि किसान को कोई भी उपज हो उनको उसका पूरा फायदा पहुँचाना सरकार का फर्ज है तभी हरियाण्याा का और सारे देश का फायदा हो सकता है।

अब मैं रोजगार के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ।

उपाध्यक्षा: आप डिमांडज पर बोल रही हैं इसलिए आप उनका हवाला देकर डिमांडज पर ही बोल सकती हैं और अगर जनरल डिमांड पर बोलना चाहें तो फिर उन पर बोलें।

श्रीमती शकुन्तला: अच्छा जी! तो मैं रोजगार के बारे में कह रही थी। आज हमारे हरियाणा में और सारे भारतवर्ष में बेकारी की एक बड़ी भारी प्रोबलम फैली हुई है लेकिन उन्होंने इस डिमांड में लिखा है कि हमने बहुत है कि हमने बहुत रोजगार फैलाया है और प्रदेश में बहुत खुशहाली आई है। मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी मैं किसी को रोजगार दिलाने के लिए लाती रही हूँ तो कोई सुनाई नही होती रही। आज तक किसी मिनिस्टर के पास से मैं एक लड़के को भी नौकरी नहीं दिला सकी हूं जब से मैं एम.एल.ए. बन कर आई हूं। पता नही उसकी यह वजह होगी कि यह अपनी पार्टी

का ही ख्याल रखते होंगे। लेकिन अगर यह बात है तो यह अच्छी नहीं है। रोजगार के मामले में पौलिटिक्स बीच में नहीं लानी चाहिए क्योंकि जो हरियाणा के नौजवान हैं उन सबको रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी है, तभी लोगों को भला हो सकता है।

हरिजन वैलफेयर विभाग को इन्होंने पिछली बार बहुत कम पैसा दिया था और जो स्कीमें वैलफेयर बोर्ड के अन्दन पहुँची थीं उनसे लोगों को बजाए फायदे के धक्का पहुँचा था और मैं समझती हूँ कि वे सिर्फ उनको बहकाने के लिए ही थी। अब भी जितना रूपया रखा गया है वह उनकी तरक्की के लिए बहुत कम है पिछली बार जब एपलीकेशन्ज आई थीं तो उनको मिला मिलाया तो कुछ नहीं था लेकिन अपनी जेब से उलटा खर्चा करके नुकसान उठाना पड़ा था। मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की स्कीमों के लिए बड़े सोच–विचार और गौर के बाद पैसा रखा जाये और पूरा पैसा रखा जाये ताकि लोगों की तरक्की हो सके। यह न हो कि इसी तरह से सारा पैसा लुटा दें और इधर उधर खुरद बुरद कर दें और नाम हरिजनों के लगा दें कि उन पर इतना रूपया खर्च कर दिया है। आज शिक्षा में क्या हाल चल रहा है? टीचर्ज को अपने घरों से बीस–बीस मील दूर भेजा हुआ है और हैडमास्टर्ज को आउट आफ दि डिस्ट्रिक्ट लगाया हुआ है। वे कुछ लोग मेरे घर पर अपने काम के लिये आये लेकिन सरकार की तरफ से उनके फोटो खींच लिये गये और उन्हें ससपैंड कर दिया गया। यह जो पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी हैं ये भी इसी तरह के

ससपैड करने का काम करते हैं। मामूली शिकायत आने पर वहां जाकर टीचर्ज को ससपैंड कर देते हैं बगैर किसी खास वजह के। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं कि पहले ससपैंड किया गया और बाद में रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। इस हालात में शिक्षा का स्तर कैसे ऊँचा आ सकता है? मैं सरकार से कहूँगी कि उनको इस बारे में सोच समझ कर कदम उठाना चाहिये और इस तरह नहीं करना चाहिये जैसा वह कर रही है। इनके ऐसा करने से हरियणा में शिक्षा का स्तर 10/15 साल पीछे चला गया है। गांव के लोगों में बच्चों को पढ़ाने का बड़ा चाव है लेकिन वे बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं क्योंकि लोग गरीब हैं। टीचर अच्छी तरह उनको पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि गवर्नमैंट ने उन पर बहुत ज्यादतियां की हुई हैं और कर रही है। वे सताये हुये हैं, उनके मन में शान्ति नहीं है और ऐसे वातावरण में वे अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते हैं इसलिए मैं सरकार से कहूंगी कि वह तबादलों के मामला पर फिर से विचार करे और जिन लोगों के साथ उनको दुश्मनी है उनके साथ ही ऐसा व्यवहार करें और सबको इस तरह तंग न करे। मेरा हलका साल्हावास का है जो कि बहुत ही बैकवर्ड ळै। जब से मैं हाउस में आई हूं मैं कहती आ रही हूं कि वहां सिंचाई के साधन दिए जायें। वह इलाका ऐसा है जो आधा सूखा है और आधा पानी में डूबा रहता हूं 10–15 गांव तो हर वक्त पानी में डूबे रहते हैं और उसकी वजह से लोगों को बहुत ही तकलीफ है। वे लोग खेती नहीं कर पाते हैं। मैं सरकार से हर साल कहती आ रही हूं कि वहां से पानी निकाल कर उस एरिया

को खुश्क किया जाये ताकि किसान खेती कर सकें। जो एरिया खुश्क है वहां पानी दें। यहां जुई कैनाल के बारे में लिखा हुआ है। इस बारे में मैं भी कहती हूं कि यह अच्छा कार्य किया गया है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि अपने सूखे खेतों में पानी ले गये और रेत के टीलों में पानी ले गये और मेरे इलाका के रेत के टिब्बे वैसे ही रह गये। वहां कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा .....

श्रीमती ओम प्रभा जैन: वहां भी हो रहा है।

श्रीमती शकुन्तला: कहती हैं हो रहा है लेकिन पता नहीं कब हो रहा है। अभी तक तो कहीं कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं कोई काम लेकर आई हूं तो उसे करने की बजाये खत्म ही किया गया है। हमारी नहरों में मोरी का मुंह 6 इंच का था लेकिन अब दो इंच कर दिया गया है। मैं समझती हूं कि एक आदमी के मुंह से पानी निकाल कर दूसरे के मुंह में पानी का गिलास लगा देना बेवकूफी है।

श्री भजन लाल: रकबे के मुताबिक मोरी का मुंह होता है।

श्रीमती शकुन्तला: दूसरों को पानी दे दिया जाये और हमारे टीलों को पानी न दिया जाये ऐसा करके इस सरकार ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। एक आदमी का अधिकार

छीन कर दूसरे को दे दिया जाये यह ठीक नहीं है और मैं इसको अच्छा नहीं समझती।

उपाध्यक्षा: अब आपका टाइम हो गया है।

श्रीमती शकुन्तला: अच्छा जी मैं अभी खत्म करती हूं। शिक्षा के बारे में मैंने निवेदन किया है और मैं कहना चाहती हूं कि मेरा हलका इतना बड़ा है कि उसमें 110 गांव हैं लेकिन उसके अन्दर एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। सिर्फ बहुझोलरी के अन्दर एक स्कूल है और उसमें भी एक दो टीचर ही रहते हैं। आप देखें कि इतने बड़े हल्का में लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई इन्तजाम नहीं है और यह कहते हैं कि शिक्षा को बहुत ऊंचा कर दिया है। अगर सरकार चाहती है कि हमारा प्रदेश तरक्की करे तो लड़कियों की शिक्षा का पूरा इन्तजाम करना चाहिये। ऐसे इलाकों की तरफ जो पिछड़े हुये हैं और जहां लड़कियों के लिये स्कूल नहीं हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाये। सिंचाई के बारे में भी कहना चाहती हूं कि मेरे हल्का में जो सिंचाई का काम जब तक मेरी वजह से और इनकी पार्टी वहां न होने की वजह से नहीं किया गया है उसको अब पार्टीबाजी में न पड़ कर करेंगे और लोगों को सिंचाई की सुविधा देंगे।

श्री रणधीर सिंह (घरौंडा): उपाध्यक्ष महोदया यह जो बजट हमारे सामने है मैं इसकी डिमांडज नम्बर 16, 9, 40, और 20 के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। हरियाणा के

मुख्यमंत्री जब लोगों के सामने जाते हैं तो बड़ी शान के साथ कहते हैं कि हमने हरियाणा की बहुत तरक्की कर दी हैं। उन्नति किस बात पर निर्भर करती है यह बजट और आपकी मांगें जो हमारे सामने हैं वे बतायेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा आज हिन्दुस्तान के लिये नहीं तमाम दुनिया में उन्नति का साधन है। हमारे हरियाणा में जितने गांव हैं वे सब ज्यादा आबादी वाले हैं और बहुत थोड़े गांव ऐसे हैं जिनकी थोड़ी आबादी है। प्रजातंत्र में यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलतें दी जायें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की उन्नति के काम लिये जाये और अगर ऐसा नहीं किया जाता तेा प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता। शिक्षा के लिये सरकार ने 20 करोड़ रूपया मांगा है लेकिन हम तो इनको इससे भी ज्यादा देने के लिये तैयार हैं अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगौं क लिये उन्नति के काम करे और गांव गांव में लोगों को लडके लड़कियों को शिक्षा की सुविधायें दी जायें। हमारे हरियाणा मे 6669 गांव हैं और इन गांवों के बारे में शिक्षा मंत्री महोदय से सवाल किया गया था कि बताया जाये कि वहां लड़कियों के लिये कितने हाई स्कूल हैं? बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को समाजवादी सरकार कहने वाली सरकार, जो यह कहते नहीं थकती कि वह लोगों की भलाई क लिये सब कुछ करने के लिये तैयार है और उन्नति के लिये सारे साधन जुटाने के लिये तैयार हैं, उसने 6669 गांव में कुल 45 लड़कियों के हाई स्कूल खोले हैं। क्या यही शिक्षा की उन्होंने की और क्या यही शिक्षा का म्यार है

जिसका ये दावा करते हैं? जहां तक मेरे हल्का की बात है मैं कहना चाहता हूं कि घरौंडा हल्का में ऐसे ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 12/13 हजार से भी ज्यादा है लेकिन वहां कोई हाई स्कूल लड़कियों के लिये नहीं खोला गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है और क्या इसकी यही वजह है कि वहां का सदस्य इनकी पार्टी का नहीं है? प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वौअ देने का अधिकार होता है और वह अपनी मर्जी का सदस्य चुन कर भेज सकते हैं लेकिन जो सरकार बनती है वह सबी बनती है और अगर किसी हल्का में इसलिये काम नह किया जाये क्योंकि वहां का मैम्बर विरोधी दल का है तो यह प्रजातंत्र के विरूद्ध बात जाती है प्रजातंत्र के बारे में बथम ने कहा है Democracy is a Government for the greatest good, for the greatest number. मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि अगर प्रजातंत्र को कायम रखना है तो यह भेदभाव की नीति बन्द करनी पड़ेगी। बगैर सिकी पार्टीबाजी के गांव गांव में लड़के लड़कियों के स्कूल खोलने चाहियें।

इसके बाद डिमांड न. 9 जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालात स्टेट में बड़ी दयनीय है। जगह जगह पर अराजकता फैली हुई है। इस अराजकता के कारण गांवों में इन्साफ की प्रणाली कायम नहीं रह सकती। गांवों के लोग कचहरियों में इन्साफ लेने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें इन्साफ नहीं मिलता। कई कई दिन तक कचहरियों के दरवाजे

खटखटाते रहते हैं। कचहरियों में सरकारी कर्मचारी गांवों के भोले भाले लोगों को इधर उधर भटकाते फिरते हैं जिससे उनके धन की हानि होती है। कर्मचारी कई तरह की बटौलेबाजी करते हैं। सरकार गवर्नमेंट मशीनरी की स्थिति को सुधारे और जनता के हित में लाभकारी पग उठाए। हमें व्यक्तिगत अनुभव है कि सरका कर्मचारी अपने काम को निपुणता के साथ निभाने में असमर्थ हैं। कर्मचारियों में इस कमी को दूर करें ताकि निर्धन व्यक्ति जो गांवों से कचहरियों में इन्साफ मांगने के लिए आते हैं, उन्हें पूर्णरूप से इन्साफ मिल सके।

अब मैं डिमांड न. 40 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो कि ऐग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के बारे में है। सरकार ने ऐग्रीकल्चर के लिए 20 करोड़ 50 लाख रूत्र रखा है जो कि मेरे विचार के मुताबिक बहुत थोड़ा है। नीलोखेड़ी में एग्रोल–इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की तरफ से ट्रैक्टर्ज की रिपेयर के लिए डिपो खोला हुआ है लेकिन किसानों को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है ताकि किसान ठीक तरह से ट्रैक्टर चला कर अपनी खेती को अच्छी तरह से उन्नतिशील कर सकें। जब सरकार ट्रैक्टर सप्लाई करती है तो ट्रेनिंग का भी कोई न कोई साधन जुटाया जाना चाहिए। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जो किसान ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करता है और ट्रैक्टर उपलब्ध करता है उसको कम से कम एक महीने ट्रेनिंग लैने की सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए ताकि ट्रैक्टर को अच्छी

तरह से चला सके और ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन कर सके और अपना सारा ध्यान खेती की तरफ लगा दे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इन तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही साथ मैंने देखा है कि ट्रैक्टरों को उपलब्ध करने में ब्लैक–मेलिंग चलती है। सरकार इस ब्लैक–मेंलिंग को चैक करने में बिलकुल नाकामयाब है। सभी जानते है कि हरियाणा कृषि प्रधान देश है और कृषि की उन्नति के लिए जो भी साधन हो सकते हैं वे सभी जुटाए जाने आवश्यक हैं लेकिन इस बजट में इतना प्रोवजिन नहीं है जिसके बल पर ऐग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कर सकें। यह बड़े खेद की बात है कि जो रूपया ऐग्रीकल्चार के लिए मांगा है, इसको मांगने के बाद भी किसान के प्रति कोई सदभावना नहीं है। ट्रैक्टरों की ब्लैक–मेलिंग बराबर चल रही है।

श्री भजन लाल: ट्रैक्टर लाटरी सिस्टम के हिसाब से दिया जाता है और वह लाटरी किसानों के सामने खोली जाती है।

श्री रणधीर सिंह: जो चीजें प्रैक्टिकल तजर्बे में आती हैं वही मंत्री महोदय के सामने रख रहा हूं। गवर्नमैंट तीन ट्रैक्टर्ज–डी.टी. 14, जीटर और बाई–लैरस सप्लाई करती है लैकिन यह ट्रैक्टर गलत आदमियों का दिए जाते हैं जिनको जरूरत नहीं होती। ये लोग बीस बीस हजार रूपये की ब्लैक करते हैं। मैं मंत्री महोदय को, अगर वे जानने के लिए लालायित हैं उन लोगों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने ब्लैक–मेलिंग की है। मिनिस्टर साहब

मुझे अश्योरेंस दे कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जासगी जिन्होंने ब्लैक मेलिंग की है और हेराफेरी की है। उपाध्यक्ष महोदया, ये बातें तो कहने की हैं कि ट्रैक्टर हम लाटरी सिस्टम से देते हैं और हेराफेरी नहीं होती। ये पेपर पर ही रह जाती है। गवर्नमेंट जनता को झांसा देती है कि हम हरियाणा की उन्नति के लिए ट्रैक्टर दे रहे हैं और तरक्की के दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन वास्वविकता यह है कि लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और जिनको ट्रैक्टर की वास्तविक रूप में आवश्यकता होती है वे वंचित रह जाते हैं। यह समझने की बात है, गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे।

गवर्नमेंट ने ऐनिमल हसबैंडरी का महकमा खोला है। इस महकमें के लिए 1 करोड़ 96 लाख रूपया मांगा है। हम मानते हैं कि हरियाणा में ऐनिमल हसबैंडरी की उन्नति बहुत जयरी है, बैलों की नसल में तरक्की होनी चाहिए, सांड़ होने चाहिए और दूध के साधन होने चाहिएं। मंत्री महोदय मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के पशुओं की नसल में क्या कमी है? हरियाणा की नसल को क्यों इगनोर किया जाता है? ठीक है जरसी सांड अमरीका से इम्पोर्ट होते है और उनके इस्तेमाल करने से दूध की मात्रा बढ़ती है लेकिन बैलों की नसल खराब होती है। क्या सरकार को बैलों की जरूरत नहीं है? क्या खेती–बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर ही इस्तेमाल करते रहेंगे? यह गलत है कि सारी की सारी खेती ट्रैक्टरों से ही की जाएगी। मैं

सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितनी लोग हैं जिनके पास पांच एकड़ जमीन है और उन पांच एकड़ जमीन को जोतेने के लिए सरकार ने ट्रैक्टर दे रखे हैं? मैंने सवाल भी पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ जमीन है और उनको ट्रैक्टर लेने के लिए लोन दिया गया? मेरे इस सवाल का जवाब नहीं आ सका। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कोई भी फार्मर ऐसा नहीं है जिसको पांच एकड़ भूमि के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध करने के हेतु लोन दिया गया हो। बहन जी, ऐसे हालात में हरियाणा की तरक्की कैसे हो सकती है? हरियाणा के बैलों की नसल अच्छी नसल है इसको सुधारने के एिल क्यों तरक्की के कदम नहीं उठाए गए? मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया और न ही उठाने के लिए तैयार है। जब कि हरियाणा के बैल अच्छे हैं तो जरसी बुल्ज लाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई? जो मिल्क सप्लाई स्कीम है उसके द्वारा दिल्ली को मिल्क सप्लाई किया जाता है। ठीक है सप्लाई करें लेकिन जो फालतू मिल्क है उसी को दिल्ली भेजना चाहिये। हरियाणा की जनता का हक छीन कर बाहर भेजना उनके साथ अन्याय है। फालतू दूध भेजने की बात बिल्कुल उचित है। सारे का सारा दूध दिल्ली भेजने का परिणाम यह है कि हरियाणा में घी 16–17 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता है और दूसरे प्रान्तों में 13, 14, 15 रूपये किलोग्राम के हिसाब से मिल जाता है। क्या यह हरियाणा में ऐनिमल हसबैंडरी की तरक्की है? महकमें वाले गांवों में जाते हैं और जो हरियाणा की नसल के

साँड होते हैं उनको निकम्मा बना देते हैं और बाहर से मंगवाए हुए सांड़ सप्लाई नहीं करते, परिणाम यह होता है कि गायें भैसें कामयाब नहीं होतीं और बाद में गलत तरीक इस्तेमाल करते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से काम न करें जिससे प्रदेश को नुकसान हो। इस महकमें में इतना पैसा खर्च करने का फायदा तब तक नहीं हो सकता जब तक गांवों में पशुओं की नसल को न सुधारें। लोगों को कोआप्रेशन दें, जो कमियां हमारे अन्दर हैं उनको दूर करें ताकि हरियाणा फले फूले। अगर सरकार चाहती है कि हरियाणा खुशहाल हो तो जो रूपया महकमें को दिया जाता है उसको अच्छी तरह से खर्च किया जाए। जो जनता की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाय तभी देश आगे बढ़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदया, सरकार सड़कों की बड़ी डींग मारती है। कहती है कि गांव–गांव में सड़क पहुंचा देगें। मेरे हल्के में घरोंडा की सड़क है जिस की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। उस रोड पर जो बस चलती हैं उनके टायर तीन दिन से ही खराब हो जाते है। कच्ची सड़क से भी बदतर हालत है। जो सदस्य कांग्रेस पार्टी में हैं उनके हलकों में तो यह सरकार सब कुछ करती है, हर डिवैल्पमेंट का काम हो रहाहै, उनकी सड़कें पहले बन सकती हैं लेकिन नान–कांग्रेस सदस्यों के हलकों की तरफ कोई ध्यान नहीं किया जाता। क्या यही डेमोक्रेसी है, क्या यही जमहूरियत है? कहा तो जाता है कि Democracy is

Government of the people, for the people and by the people. परन्तु हमारे यहां एक ही पार्टी की हकूमत चलती रही और इसी एक ही पार्टी की बहबूदी के लिए काम होता रहा है और दूसरे इलाकों को इग्नौर किया जाता रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं विशेषतः वित्त मंत्री महोदया से आश्वासन चाहता हूं कि घरौंडा हल्के की इस सड़क में जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। मुझे निहायत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस सड़क की हालत पहले से भी खराब हो चुकी है।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): जब अगले इलैक्शन के लिए जाएंगे तब बनायेंगे।

श्री रणधीर सिंह: अगला इलैक्शन होगा या न होगा, यह भविष्य बतलाएगा। आज देश के हालात बहुत खराब हैं, ऐसे हालात में नहीं कह सकते की कौन पार्टी आएगी, कौन नहीं आएगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि जनता की सन्तुष्टि की बात ही न हो। अभी पिछले दिनों की बात है। एक सड़क के बारे में हमने मिनिस्टर महोदय को बताया लेकिन जनता की आवाज सुनी नहीं जाती। जनता की बात को ठुकराया जाता है ओर अपनी मनमानी करने की कोशिश की जाती है। हम चाहते है कि जनता की सही मांगों को माना जाना चाहिए और सही अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। जम्हूरियत के अन्दर किसी भेद–भाव के यह सदस्य विरोधी दल का है और यह अपनी पार्टी का है, सभी लोगों का काम किया जाना चाहिए। अभी हमने

मार्किटिंग बोर्ड के बारे में बात सुनी। यह ठीक है कि मार्किटिंग बोर्ड बहुत काफी काम कर रहा है लेकिन यह महोदय जो उसके अधिकारी यहैं केवल उन्हीं हलकों में सड़क बना रहे हैं जहां उनके अपने सम्बन्धी हैं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर यह सइ तरह से काम करती रहेगी तो लोग समझ कर यह बात आपके सामने रख देंगे कि इस तरह की सरकार हमको नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह जनता की सही बात को सही तरीके से अमल में लाए ताकि जनता की भलाई हो सके। इन शब्दों के साथ, मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

चौ. बनवारी राम (जुंडला, एस.सी.): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज बजट पर बोला जा रहा है। इस बारे जो बजट हमारी सरकार ने बनाया उसकी मैं ताईद करता हूं लेकिन साथ ही साथ मे। कुछेक बातें यहां अर्ज करना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज 23 साल हो गए हैं हमारे मुल्क को आजाद हुए। आप हिसाब लगाएं कि 23 सालों मैं कितने दिन हुए और इन दिनों में कितने बार रेडियों से खबरें आई होगी? इन 23 सालों में आप सच मानिए लोग हिन्दुस्तान के सब लीडरों के मुंह से चाहे वह अपोजीशन का है और चाहे सरकारी पार्टी का है, तथा रेडियो से ''हरिजन'' ''हरिजन'' ''हरिजन'' की रागनी सुनकर तंग आ गऐ

हैं। यह तो जनसंघ भी गीत गा रहा है और स्वतन्त्र पार्टी भी गीत गा रही है कि समाजवाद लायेंगे।

श्रीमती शकुन्तला: रिपब्लिकन पार्टी भी गा रही है।

चौ. बनवारी राम: ठीक है रिपब्लिकन पार्टी भी गा रही होगी लेकिन कांग्रेस भी रिपब्लिकन है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष: आप अपनी स्पीच करें।

चौ. बनवारी राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके लिए मैं केवल सरकार की ही खता नहीं समझता बल्कि सभी पार्टियां बराबर की दोषी हैं। क्योकि सारी पार्टियां 23 साल से इस तरीके के गीत गा रही हैं और जनता को धोखा दे रही हैं। कल मेरे साथी कवर सिंह दहिया ने कहा था कि 6 महीने के अन्दर बगावत आएगी, क्रान्ति आएगी, मैं उसमें शामिल हूंगा। मैं अपने साथी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर क्रान्ति की जरूरत नहीं है। यहां 15–16 एम.एल.एज. आज भी हरिजन हैं और अगर सब मिल कर हरिजनों को तकलीफ से छुड़ाना चाहें तो तीन दिन नहीं लगेंगें। मरग हममें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम सब आराम करना चाहते हैं और फीकी बातें करते हैं। अब इलैक्शन होगा। हमारा फर्ज है कि सरकार के नुमायदे चुनवा कर लायें। उसके बाद सभी मंत्री साहेबान या जितने एम.एल.एज. हैं एक दिन सरकार के पास जायें ओर अपनी तकलीफ उनके सामने रखें। सवाल ही पैदा नहीं होता अगर दस साल के अन्दर जो काम नहीं

हुआ वह दस दिन के अन्दर न हो। सरकार को हमने खुद बिगाड़ा है क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है।

आज मजदूर औरत, मर्द और बच्चे–बच्चियां बर्फ में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं, टोकरियां सिर पर ले लेकर सड़कें बनाते हैं, नहरें खोदते हैं, बिल्डिगें बनाते हैं लेकिन उसे मजदूरी, अढ़ाई, साढ़े तीन और चार रूपये से ऊपर नहीं मिलती। हम लोग तो आराम से रहते हैं। जहां जाते हैं वहां सेवा होती है लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि आज भी मजदूर जो बर्फ में, सर्दी, गर्मी और वर्षा में सारा दिन काम करता है वह दो वक्त पेट भर कर रोटी नहीं खा सकता, कपड़े की तो बात ही कया करनी है, क्योंकि उसकी मजदूरी बहुत थोड़ी है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा किसी भी मजदूर की मजदूरी चाहे वह किसी भी महकमे में काम कर रहा हो पांच रूपये से कम नहीं होनी चाहिए बल्कि पांच रूपये से ऊपर ऊपर ही होनी चाहिए।

सरप्लस जमीन के बंटवारे का जहां तक, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सम्बन्ध है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कहां से जमीन दिलायेगी आज तो हालत यह है कि कोई पोते के नाम सरप्लस जमीन को करवा रहा है और कोई बहु के नाम करवा रहा है। जमीन कहां से मिलेगी जब कि उसे इस तरह से छिपाया जा रहा है? यदि सरकार कोई इसत तरह का ऐक्ट बना दे कि सारी की सारी सरप्लस जमीन को भूमिहीनों को दिया जायेगा तब तो कुछ हो सकता है वरना जमीन छुपाई जा रही है। इस हाउस में

भी कुछ नुमायदे बैठे हैं जो इस तरह से जमीन को छुपा रहे हैं। (विघ्न) राठीक साहब, शायद आप को कुछ दर्द हुई होगी क्योंकि शायद आपका पड़ोसी जागीर का मालिक होगा।

चौ. जय सिंह राठी: मेरे पास तो एक बिसवा भी जमीन नहीं है, मैं भी हरिजन हो रहा हूं।

चौ. बनवारी राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जमीन बंटेगी अवश्य लेकिन कुछ देर लगेगी। कंवर सिंह दहिया जो कहते हैं कि क्रान्ति आनी चाहिए उस क्रान्ति को हम 15–16 एम.एल.ए. भी ला सकते हैं। क्यों हम दूसरी क्रान्ति का नाम लें? हम तो खुद सरकार को मजबूर कर सकते हैं, तीन दिन के अन्दर सब कुछ कर सकते हैं। यह नहीं होना चाहिए कि कोई तो विशाल हरियाणा पार्टी का गीत गाता रहे और कोई कांग्रेस का गाता रहे। हरिजन के नाते इकट्ठे होकर हम अपनी तकलीफों का बतला सकते हैं। यह बात तो इनके अन्दर है नहीं – (विघ्न) –

एक आवाज: सूबेदार साहब के पास कह दो।

चौ. बनवारी राम: सूबेदार साहब इस वक्त हमारे लीडर हैं। उनके ऊपर हमें नाज है। इन्हीं के पास हमने कहना है या फिर सी.एम. साहब के पास कहना है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां कहा गया कि मुजारे बेदखल नहीं होगे। कोन कहता है कि नहीं होंगे? मुजारे इतनी बुरी तरह से बेदखल हो रहे हैं जिसका कोई शुमार नहीं। जब रोकने का काम आता है तो सरकार कह देती है

कि अदालत का केस है। भला अदालत में चौ. राठी के ***** वगैरा जो बैठे हैं वे कैसे गरीबों को जीतने देंगे? यह मुजारा ऐक्ट ठीक है। जो मुजारा यहां बैठा है तक तक बेदखल नहीं होगा जब तो उसे दूसरी जमीन नहीं मिल जाएगी।

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि मेरे ***** इन मुजारों को बसने नहीं देते, इसके बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा।

चौ. बनवारी राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, राठी साहब बहुत समझ गए हैं। मैं तो सबको कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्षा: आप नाम न लें।

चौ. बनवारी राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर यह बात कानून के बाहर जाती है तो मैं इन लफ्जों को वापस लेने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्षा: ऐक्सपंज कर दिए जायें।

चौ. बनवारी राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा पंचायतों की जमीन के विषय में सरकार ने एक्ट बनाया लेकिन हरियाणा में जहां बड़े बड़े गांव हैं वहां पर तीसरे हिस्से की जमीन नहीं दी जाती है। सरकार के यह भी नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो

पंचायतों की जमीन तीसरे हिस्से में मिलती थी उससे भी हमें महरूम किया जाता है उसको भी अपने आप लोग बो लेते हैं।

उपाध्यक्षा: आप तो पहले भी बोल चुके हैं। इसलिए जल्दी खत्म करें।

चौ. बनवारी राम: मैं ज्यादा टाईम नहीं लेना चाहता हूं। दोबारा फिर बोल लूंगा। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार का जो कानून है, हमारी सरकार ने जो चीजे बजट में रखी हैं मैं उनकी ताईद तो करता हूं लेकिन वे पूरी नहीं होती है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वे पूरी होनी चाहिए। आजकल जो मुजायरे बेदखल किये जा रहे हैं उनकी बेदखली को रोका जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं और अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मैं अन्त में यही कहूंगा कि अगर हरिजनों को उनके हको से महरूम किया जाता है तो इसमें हरिजन लीडर और हरिजन एम.एल.ए. कसूर वार हैं। हरियाणा के हरिजनों के हकूक की जिम्मेदारी हम 16 एम.एल.एज. की है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: मै आपसे यह जानना चाहूंगी कि आप मुझे बोलने का कितना टाईम देगें?

उपाध्यक्षा: आधा घन्टा आपको मिल जायेगा।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आधा घन्टा तो बहुत कम टाईम है।

उपाध्यक्षा: स्पीकर साहब ने कहा है कि साढ़े बारह बजे गिलोटिन लागू करना है। इसलिए इतना ही समय मिलेगा।

महन्त गंगा सागर (झज्जर): डिप्टी स्पीकर साहिबा आपने बजट की डिमान्डज पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए तो आपका धन्यवाद लेकिन समय बहुत थोड़ा है। फिर भी इस कम समय के अन्दर ही चन्द सुझाव मैं सदन के सामने रखूंगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा सरकार ने फरमाया है कि एग्रीकलचर के लिए बजट में खास हिस्सा रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं, रखा गया है लेकिन जैसा कि रामधारी जी ने फरमाया कि बहुत से मैम्बर्ज अपोजीशन का ही रोल अदा करते हैं और महज क्रीटिसाइज करते हैं। उस बात को मदेनजर रखते हुए मैं अपनी तरफ से कुछ ठोस चीजें रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार उन चीजों की तरफ जरूर ध्यान देगी।

जरायत के अन्दर हमारी स्टेट काफी प्रधान स्टेट हैं और हमारी स्टेट का बहुत बड़ी सैक्शन जरायत पर निर्भर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा किसान आज हिन्दुस्तान के काफी जागृत किसानों में हो चुका है। उसको कुछ सरकार की तरफ से भी जागृत किया गया और कुछ अपने आप भी वह जागृत हुआ है। आज किसान का जागृत होने का कुछ कारण भी है

कयोंकि पहले जो किसान थे उनको अपनी उपज का मुआवजा भी नहीं मिलता था जबकि आजकल कुछ जिन्सों के अन्दर उसको कुछ माकूल मुआवजा मिलता दिखाई दे रहा है। किसान अपनी तरफ से भी खड़ा हुआ है। गेहूं का एक बैलैन्सड प्रोडक्शन है और उसके भाव में भी सुधार हैं, इसलिए हम कारण से किसान गेहूं बोने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। किसान को यह तसल्ली हो चुकी है कि गेहूं से कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन आज के मंहगाई के हिसाब को देखते हुए, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिकल किसान हूं अगर किसान एक एकड़ गेहूं बोता है तो उसके अन्दर पांच सौ से लेकर 600 रूपये तक एक एकड़ पर किसान का खर्चा आ जाता है। मौजूदा भाव के अनुसार 20 मन गेहूं उसका खर्चा के अन्दर चला गया। अगर उन किसान को पचास या 45 मन मिला है तब भी यह समझियेंगा कि उसको माकूल मुआवजा मिला है। अगर वही किसान खुद काश्त न करे और दूसरे भाई को बांटे पर दे दे तो उसको चौहद–पन्द्रह मन एक एकड़ में मिलता है क्योंकि 20 मन तो उसका बोने और दूसरे खर्च में आ गया। 15 मन दूसरे के हिस्से में चला गया तो इस प्रकार से बहुत कम हिस्सा मिलता है। किसान को तो तब फायदा होगा जब इम्प्रूवड वैरायटी हम काश्त करें। हम उससे 35 मन से ज्यादा कमा सकते हैं बशर्ते कि हमारे पास साधन हों।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे हरियाणा में बिजली दी है। बहुत से साथी भले ही यह कहें कि नहीं दी लेकिन मैं इस

बात से सहमत नहीं हूं। हरियाणा के लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। अगर कोई गांव अपनी मर्जी से रह गया हो तो यह दूसरी बात है लेकिन इस बात में संकोच करें कि सारे हरियाणा में बिजली नहीं पहुंची यह गलत बात है। लेकिन देखने में यह आता है कि बिजली की मेनेटेनेन्स की दिक्कत है। वह कैसे हल हो? इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। अगर आपके पास स्टाफ उतना नहीं है जितना होना चाहिए तो उन जरूरतों को मदेनजर रखते हुए पहले आपको यह कहना चाहिए कि आप पूरा स्टाफ रखें और दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि जो बिजली का सामान तार या अन्य कोई भी चीज लगी है वह अच्छी क्वालिटी की लगनी चाहिए। पहले जो सामान लगा है वह इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। यह जो रोज राजे खराब हो जाने वाली दिक्कत है यह नहीं आनी चाहिए।

मैं खुद किसान होने के नाते से आपको याद दिलाता हूं कि अगर यह महीना बीस दिन पहले जो बरसात हुई है यह नहीं होती तो हरियाणा की गेहूं की फसल को बहुत धक्का लगता। कई जगहों पर इससे पानी की जरूरत पूरी हो गई है। नहरों और टयूबवैलों से कई एक किसान तो अपनी पूरी फसल को एक भी पानी नहीं दे सके हैं। इसलिए आपके जरिए सरकार से निवेदन करूंगा कि बिजली की मेटेनैन्स के विषय में यह गौर करें ताकि किसान अपनी पूरी पैदावार कर सके।

यहां हाउस में भी ट्रैक्टरों के विषय में जिक्र आया। मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकता कि ट्रैक्टर कम क्यों आ रहे हैं, हमारी ऐग्रोइन्डस्ट्री की कमी है या बाहर से इम्पोर्ट होकर नहीं आ रहे हैं या हिन्दुस्तान में ही ट्रैक्टर नहीं बन रहे हैं और अगर बन रहे हैं तो उसका उचित हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उनको दूर करके किसानों को जरायत का पूरा सामान दिया जाये। आजकल फर्टेलाइजर की तो इतनी दिक्कत नहीं है। वह तो तकरीबन मिल रहा है। मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर किसान को पानी, ट्रैक्टर और खाद समय पर मिल जाए तो किसान अपनी पैदावार को बहुत बढ़ा सकता है। इसलिए मैंने जो ये सुझाव दिये हैं इसमें कोआपरेटिव और दूसरे कई विभाग आ जाते हैं, सुझावों पर सरकार को गौर करना चाहिए और जो कमी है उसको दूर करना चाहिए।

ट्रांसपोर्ट का जहां तक सम्बन्ध है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको नेशनेलाइज कर दिया है और जो थोड़ी–बहुत बाकी है उसको भी जल्दी ही नेशनेलाइज कर दिया जायेगा। कुछ बसें प्राईवेट चल रही हैं। उनका कुछ लाभ नहीं है इसलिए उनको भी सुधार करना चाहिए। जब सरकार ने अपनी बसों को चला दिया है तो उनके लिए हर गावं में बसे स्टैन्ड बनने चाहिए। हर गांव के बस स्टैन्ड पर टाईमटेबल होना चाहिए ताकि लोगों को इस बात की दिक्कत न पड़े कि बस किस सयम पर आती है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मैं एक चीज और कहूंगा उसको

उतारा नहीं गया। इस तरह से सर्दी में पंखे लगे हुए हैं उनको उतारा नहीं गया। इस तरह से सर्दी में पंखे लगे रहें तो वे खराब ही होते हैं। इसलिए उनको उतार देने से महकमें को कुछ न कुछ बचत ही होगी।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिमान्डों में कुछ जिक्र है। जहां तक हमारी स्टेट के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है वह और स्टेटों से तो अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ कमियां है। जैसे बंगा की स्टेट है उससे तो हम अपनी स्टेट को कम्पेयर नहीं करेंगे। यहां की जनता बड़ी अमनपसन्द है और न ही यहां पर इतने झगड़े ही होते हैं। लेकिन फिर भी जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ सुधार करने की जरूरत है। हमारे अफसर जो अब काम पर लगे हुए हैं वे और ज्यादा ध्यान करेंगे ताकि छोटी छोटी जो भी दिक्कतें हैं वे भी दूर हो सकें।

अभी ऐग्रीकल्चर की मैं एक बात भूल गया हूं जिसे मंत्री महोदय नोट करें। जो माल मंडियों से खरीदा जाता है उसमें जो महकमें उसे खरीदतें हैं बहुत गड़बड़ी करते हैं और वह गड़बड़ी यह है जैसे किसी स्टेट को भेजने के लिए वहां से माल खरीदा जाता है और वहां से सीधा उस स्टेट को भेज दिया जाता है लेकिन वे खरीदने वाले अपने कागजों में फालतू एन्टरीज दिखा देते हैं जैसे मंडी से माल खरीद कर लोड कराया, गोदाम में रखा गया, गोदाम से रेलवे स्टेशन भेजा गया। ये जो लोकल कार्टेज की एन्टरीज ये अधिकारी कागजों में दिखाते हैं इससे वे लाखौं

रूपये खा जाते हैं। मगर आप इस चीज की चैक करें तो लाखों रूपये की बचत हो सकती है।

श्री भजन लाल: मैं किसी का नाम लेकर शिकातय नहीं करना चाहता। इन्डस्ट्रीज का जहां तक ताल्लुक है हरियाणा के अन्दर इसके लिए बहुत गुंजाइश है। हमारी स्टेट एक ऐसी जगह पर वाक्या है जिससे दिल्ली के तीनों तरफ हम आ जाते हैं। यहां के मजदूर भी काफी मेहनती हैं। जितना इस स्टेट के अन्दर एक्सपेन्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कुछेक इन्डस्ट्रीज ऐसी देखी गई हैं जैसे कालका में मेज फैक्ट्री लगी है। इस फैक्ट्री के लगने से एक गलत बात हुई है। वह किसी एक आदमी को खुश करने के लिए लगाई गई है। अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे यहां लगेगी तो हमारी स्टेट तरक्की नहीं करेगी। ऐम्पलाएमैंट का हरियाणा के अन्दर जहां तक ताल्लुक है, वे आंकड़े जो हमारी फाइनैंस मिनिस्टर साहिबा ने दिए हैं बहुत कम मालूम पड़ते हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है कि 239603 से बढ़ कर 259433 हो गए है। इसके अलावा हमें कई प्रतिशत ऐम्पलाएमैंट मिले तो हरियाणा का गुजारा हो सकता है। इसके बारे में मैं एक उदाहरण देता हूं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जरा गौर करें और तफतीश करायें। रोहतक का जो का ट्रांसपोर्ट डिपो है उसके अन्दर कन्डक्टरों की वैंकैन्सीज निकलीं। ऐम्पलायेमैंट ऐक्सचैन्ज की मार्फत नाम मंगवाये गए। कुछ लोगों ने इन्टरव्यू दिया और उनको सिलैक्ट कर लिया गया। उसके बाद महकमें वालेा ने

उनकी चिट्ठी लिखी कि आप ट्रेनिंग ले लें और उन्होंने एक महीने की ट्रेनिंग ले ली। महकमें वालों ने अपनी तरफ से उनके सर्विस की सिक्योरिटी भी दे दी, उनके करैक्टर वैरिफाई करवा लिए गए, वे नौकरी के काबिल हो गए, लेकिन जब उनको ऐसे ही 8–10 महीने हो गए तो उसके बाद, 11 कंडक्टरों को कह दिया कि चूंकि 6 महीने हो चुके हैं अब दोबारा ऐम्पलायेमेंट में नाम दर्ज करवाओ और फिर यहां दरख्वास्त दो। इस तरह की ट्रेनिंग के बाद नौकरी से इन्कर किया जाए तो इससे लोगों में असन्तोष फैसता है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करूंगा कि अगर यह बात दुरूस्त हो तो इसकी तहकीकात करायें।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोलता हुआ मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा कि चण्डीगढ़ का जिक्र यहां आया। यह चाहे किसी की गलती से ही हुआ, चाहे अपोजीशन की गलती से हुआ, चाहे यह सरकार की गलती से हुआ लेकिन यह मौका इस बहस को लाने का नहीं है। अब तो सिर्फ इस बात की तरफ गौर करना चाहिए कि जो फाजिल्का का इलाका है वह हमको मिले। वह हमको एक साल के अन्दर ट्रांसफर होना था। मेरे ख्याल में सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक सैंटर को कुछ नहीं लिखा जब कि एक साल बीत चुका है। उसके लिए सरकार को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए क्योंकि एक साल के बाद यह बात हो जाएगी कि आप फाजिल्का भी नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए इसकी तरफ सरकार को फौरी तौर पर कोई कदम उठाना चाहिए। अब मैं अपनी बात

को खत्म करते हुए सिर्फ एक ही रिक्वैस्ट करूंगा कि सब कंस्टिच्वैंसिज के साथ, चाहे वे अपोजीशन की हैं या चाहे कांग्रेस की हैं, एक जैसा सलूक सरकार को करना चाहिए क्योंकि जनता सभी एक है इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कटार सिंह छोकर पदासीन हुए)

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): चेयरमैन साहब, बजट पेश करते हुए मैंने सरकार की ओर से कहा था कि हमारा यह साल प्रगति की दृष्टि से बड़ा ऐतिहासिक और बहुत शानदार रहा। कल से बजट पर बहस हो रही है और काफी मेम्बरों के इस पर ख्यालात आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि हमारे साथियों ने बड़े रचनात्मक सुझाव दिए हैं, उन की बातों का जवाब देते हुए मैं खास तौर से सरकार की यह भी खुशी व्यक्त करना चाहती हूं कि हमने पिछले दो तीन सालो में अपनी प्राकृतिक कमियों पर काफी काबू पाया है और आज हम ऐसे मरहले पर खड़े हुए हैं जिसे हम ही नहीं बल्कि सारा देश इस बात की आशा करता है कि हरियाणा का भविष्य बड़ा उज्वल है। चेयरमैन साहब, हमारे अगले वर्ष में दो सौ एक (201 करोड़) करोड़ रूपये के खर्चे का अनुमान है। चालू साल में यह खर्चा 175 करोड़ रूपये का था। आप देखेंगे कि हर साल हम 25–26 करोड़ रूपया साल का बढ़ौतरी कर रहे हैं और हमें यह बात भी माननी होगी कि हरियाणा राज्य एक ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने अपने साधन

लोगों पर बोझा झाल कर नहीं इकट्ठे किये हैं बल्कि यहां पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर का एक इतना खूबसूरत समन्वय हुआ है कि जिसके द्वारा हमने अपने साधनों में बड़ी भारी तरक्की की है और साथ ही साथ यह केवल दो सौ एक करोड़ रूपये की बात नहीं है जैसा कि बजट के खर्च का अनुमान है बल्कि अपनी बात के दौरान मैं बताऊगी कि हरियाणा में इससे बहुत ज्यादा कई करोड़ रूपये की इंवैस्टमेंट हो रही है जिससे हमारे साधारण किसानों और छोटे एन्अरप्रिन्योर्ज को फायदा पहुंचने वाला है। चेयरमैन साहब, पिछले दो सालों के अन्दर हमारे यहां कई कारपोरेशन बनीं और उससे पहले भी कई चल रही थीं और मुझे इस बात की खुशी है कि उनका काम अब एक बहुत अच्छे ढंग से चल पड़ा है। हमारे यहां इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन है, उसका जिक्र बजट स्पीच में आया था कि उसने कई अच्छी अच्छी इन्डस्ट्रीज हाथ में ली हुई हैं। इसी तरह से डैरी डिवैल्पमेंट कारपोरेशन बनी। जींद में आपने देखा एक मिल्क प्लांट बना। अब भिवानी में दूसरा बनने जा रहा है। अम्बाला शहर और अम्बाला कैन्ट में हम मिल्क की सप्लाई को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे यहां फाईनैन्शियल कारपोरेशन है, उसका भी जिक्र आया कि उसने इस साल लोगों को दो करोड़ रूपये के करीब कर्जा दिया है। ट्रांसपोर्ट का नैशनेलाईजेशन हुआ, उससे भी हमारी आय में बहुत तरक्की हुई है। इसी तरीके से लाट्री की स्कीम भी है और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि हरियाणा राज्य में लाटरी का काम बहुत अच्छे ढंग से हुआ और हमें तकरीबन 1.13 करोड़ नेट इन्कम

होने की आशा है। इन्हीं चीजों से हाउस को इस बात का अंदाजा लग सकता है कि तीन साल पहले हमारी आय रैवन्यू साइड पर 61 करोड़ रूपये की थी और बजट पेश करते हुए मैंने कहा है कि यह इन्कम अब 113 करोड़ की हो जाएगी। 52 करोड़ रूपया तीन साल के अन्दर 12.00 noon रिसीटस साइड पर बढ़ जाये जबकि कोई नया टैक्स या कोई खास भार लोगों पर न डाला हो तो मैं समझती हूं कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति के लिए इससे बेहतर चीज कोई ओर नहीं हो सकेगी। कल सिंगोल साहब ने काफी जोश–खरोश के साथ कहा कि यह स्टेट कर्जे के नीचे दब रही है। उन्होंने कहा कि यह 11 करोड़ का ही डैफिसिट नहीं है बल्कि यह तो पचासों करोड़ में जाकर डैफिसिट पड़ जाएगा। मैं उनको बताना चाहती हूं कि लोन लेना या पब्लिक डैटस जो हैं, यह फाइनैन्स का ही एक ऐक्सैप्टिड प्रिसिंपल है और उन्होंने तो बिजनैस करके भी देखा है। आपको बिजनैस करना हो, इन्डस्ट्री लगानी हो, खेती में इन्वैस्टमैंट करनी हो, ऐसे बहुत से काम लोन से ही चलते हैं। यह जरूर देखना चाहिए कि आपका लोन प्रोडक्टिव परपजिज के लिए हो। चेयरमेन साहब, लोन तो उसी को मिलता है जिसकी कोई साख हो। इन जैसे लोगों को तो कहीं ये अगर मांगने चले जायें, एक पैसा भी न मिले। हमारी जो रिसीटस में इतनी इम्प्रूवमैंट हुई है, वह इसलिए हुई है कि हमारा एक्सपैंडीचर बड़ा प्रोडक्टिव था। एग्रीकल्चर पर था, इंडस्ट्रीज पर था, इरीगेशन पर था, ड्रेनेज पर हुआ और इलैक्ट्रिसिटी पर हुआ। इसी वजह से हमारी रिसीटस बहुत इम्प्रूव हुई हैं। जहां तक लोन्ज

का सवाल है, हमने लोन्ज लिए भी हैं और हर साल हमको री–पे भी बहुत करने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि भाखड़ा के लिए कितनला कर्जा लिया गया था। वह हम हर साल री–पे भी करते हैं। दस–दस, बारह–बारह करोड़ रूपया हमको हर साल देना पड़ जाता है। और भी मल्टीपरपज प्रोजैक्टस के लिए लोन था या दूसरी चीजों के लिए लोन था, वह भी हमें री–पे करना पड़ता है। 1966–67 में मैं आपको बताना चाहती हूं कि फाईव मन्थस में हमने 2 करोड़ 35 लाख रूपया वसूल किया था जबकि हमने लोन की री–पेमैंट 8 करोड़ और 49 लाख रूपये की थी। 1967–68 में 20 करोड़ 7 लाख रूपया हमने लोन का रिसीव किया 19 करोड़ 91 लाख रूपया हमने वापस किया। 1970–71 में 50 करोड़ रूपया हमने रिसीव किया और 40 करोड़ के करीब हमने वापस किया। इसी तरीके से 1971–72 में हम 60 करोड़ रूपया लोन लेंगे और 42 करोड़ से भी ज्यादा का वापस करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहं हम लोन लेते हैं, हर साल उसको या पिछले लोन को वापस करने के लिए भी हमें बहुत भारी रकम अपने बजट में रखनी होती है और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी हे बावजूद इस बात के, कि हमारे स्टेट में इतने खर्चे हो रहे हैं, आाज तक कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि हमें रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट करने की जरूरत पड़ी हो। राजस्थान या दूसरी स्टेटस में आप देखिए। वहां इतना ओवर ड्राफ्टिंग हो जाता है कि कई बार स्टेट को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन हरियाणा में इन सब तरक्कियों के बावजूद भी हमने बहुत

इम्प्रूवमेंट की है। (विघ्न) स्पीकर साहब, सिर्फ पब्लिक लोन्ज की ही बात नहीं है, हमारी रिसीटस साइड में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। कल हमारे भाई सिंगोल साहब, यह भी कह रहे थे कि बहुत से टैक्सिज आर्डिनेन्सिज के जरिए लगाए गए हैं। मैंने तो सारे ही टैक्स मंगा लिए हैं। सिर्फ एक टैक्स हमने जरूर आर्डिनेन्स के जरिये लगाया था और वह पैसेजर्ज एंड गुडज टैक्स है। इसे हमने 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत किया है। बाकी सबके लिये ऐक्ट में हमारे पास खुद ही पावर थी .....

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब, पहले इसी हाउस में स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी कि हाउस में बोलते हुये किसी भी मैम्बर को उसके नाम से या भाई वगैरा कह कर आप नहीं बुला सकते। मैं फाईनैन्स मिनिस्टर साहिबा से कहूंगा कि वह सिंगोल साहब को भाई न कहें। बल्कि आनरेबल मैम्बर या किसी और ढंग से ऐड्रैस करें। इस बात पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि आया उन्हें जो वह कह रही हैं, वह कहना चाहिए या जो मैंने कहा है वह कहना चाहिए? .....

श्रीमती ओम प्रभा जैन: चेयरमैन साहब, मेरे भाई अगर इस बात से बुरा मान गये तो और किसी तरीके से तो मैं सम्बोधित करने से रही .....

चौ. जय सिंह राठी: क्या कहा जी आपने? मैंने सुना नहीं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आप एक छोटी सी बात पर बुरा मान गये और खुा हो गये .....

चौ. जय सिंह राठी: नहीं जी। मैं तो हाउस की प्रथा चाह रहा हूं। होम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐतराज किया था जब मैंने उन्हें साहब कह कर पुरार दिया था .....

श्रीमती ओम प्रथा जैन: चेयरमैन सहाब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 201 करोड़ रूपये के खर्चे का अनुमान है लेकिन इसके साथ ही साथ जो बहुत सी करोड़ों रूपये की इन्वैस्टमैंट हमारी स्टेट में होने वाली है वह कोआप्रेटिव लोन्ज एग्रीकल्चरल रिफाइनैन्स कारपोरेशन और मौरगेज बैंक के जरिये होनी है। मैं हाउस की इत्तलाह के लिए बताना चाहती हूं कि सन् 1966–67 में हमने कोआप्रेटिव बैंक से जो लोन किसानों को दिया, वह 5 करोड़ 97 लाख रूपये का था, 1967–68 में 9 करोड़ 66 लाख का था, 1968–69 में 28 करोड़ 35 लाख था। जरा अन्दाजा कीजियेगा। 1969–70 में यह 37 करेाड़ 8 लाख हो गया है। तो 1967–68 में जो लोन 9 करोड़ दिया वह 1969–70 में आकर 37 करोड़ का हो गया। यह जो 28–29 करोड़ रूपया लोगों में गया, वह प्रोडक्टिव परपजिज के लिए प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से लैंड मोरगेज बैंक के द्वारा जो कर्जा दिया गया वह 1967–68 में 2 करोड़ 67 लाख रूपया था और 1969–7. में 7 करोड़ रूपये था तकरीबन 4.50 करोड़ रू. की बढ़ौतरी यहां पर हुई। 37 करोड़ रूपया कोआप्रेटिव बैंक्स के जरिए और 7 करोड़ रूपया लैंड

मोरगेज बैंक के जरिए, तकरीबन 4.4 करोड़ रूपये की और इनवैस्टमैंट हमारे खेती के सैक्टर में हुई। मुझे यह बात भी कहते हुए खुशी होती है कि लैंड मोरगेज बैंक के जरिए जो कर्जा दिया, उससे हमारे आम किसानों को बहुत फायदा पहुंचा। 16917 टयूबवैल्ज लैंड मोरगेज के पैसों से लगाये गए। 17 हजार टयूबवैल्ज की मदद अगर इन बैंकों से मिल जाय तो आप अन्दाज कर सकते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल इकानोमी में कितना इजाफा हो सकता है। इसके अतिरिक्त लैंड मोरगेज बैंक के कर्जे के द्वारा 2324 ट्रैक्टर्ज खरीदे गये और 250 एकड़ जमीन पर ग्रेप कल्टीवेशन किया गया। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस साल हमने कई प्रोग्राम स्टेट के अन्दर शुरू किये और उनमें कामयाबी हासिल की। आज सारा देश जानता है कि हरियाणा राज्य में गांव–गांव में बिजली पहुंच गई है और उसके लिए हमें करोड़ों रूपये के साधन जुटाने पड़े। आज उस बिजली का फायदा सिर्फ खम्भों और तारों में नजर आये, यही बात नहीं है। विज्ञान के लितने साधन हैं ओर हम सब समझते हैं कि दो साल के बाद इन खम्भों का और तारों का कितना बड़ा इन्कलाब हरियाणा में सामाजिक, हरियाणा की आर्थिक और हरियाणा की हर किस्म की जिन्दगी में आने वाला है। इन्हीं सालों में सड़कों का कितना बड़ा भारी क्रैश प्रोग्राम शुरू हुआ और शुरू ही नहीं हुआ बल्कि जो बात यहां हाउस मे ंकही गई, उसे ज्यादा कामयाबी हासिल की गयी। हमारी सरकार ने सिर्फ 2000 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात की थी। सम्भव है कि हम

2000 से भी ज्यादा पर पहुंच जायें। इसी तरीके से बैकवर्ड एरियाज में, ड्रोट अफैक्टिड एरियाज में जो इरीगेशन की स्कीमज चालू हुई, उनसे एक नई राहत उन पिछड़े इलाकों से मिली। इस साल एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि वर्ड बैंक की टीम हरियाणा को विजिट करने के लिए आई और हमने उनको लगभग 35 करोड़ की स्कीमें दी हैं। हमारे काम को देखकर उन्होंने बहुत संतोष प्रकट किया और वर्ड बैंक टीम के पास सारे हिन्दुस्तान से जो स्कीमें गई हैं, हरियाणा एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी नम्बर दो पर है। उन्होंने हमसे एक आश्वाशन भी दिया है और हम आशा करते हैं कि 10 हजार टयूबवैल्ज, 7000 ट्रैक्टर्ज 10 हार्वेस्टर्ज और तकरीबन 50 स्प्रिन्कलर्ज सैट हमें उनसे मिलेंगी जिससे हमारी खेती को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। (इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुई)

उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले साल जब हमने वार्षिक योजना प्रस्तुत की थी तो 41 करोड़ रूपया खर्च करने की बात की थी जबकि उस समय हमारा डिफिसिट 12 करोड़ 50 लाख रूपया था। उसके बाद आठ–नौ करोड़ रूपया और भी प्लानिंग स्कीम पर खर्च किया और हमारी प्लान 49 रूपये की बनी। 49 करोड़ रूपये की प्लान होने के बावजूद भी हमारा डैफिसिट साढ़े 12 करोड़ से घट गया और वह सात करोड़ रहा जबकि कैपिटल ऐक्सपैंडिचर में या प्लान ऐक्पैंडिचर में कहीं भी शार्टफाल नहीं हुआ। इस बात से आप

अन्दाजा लगा सकती हैं कि हमारी स्टेट की पोजीश कया ळे, स्टेट के साधन सीमित होने के बावजूद भी हमारा प्लान बड़ा सकसेसफुल है। आज हिन्दुस्तान में हरियाणा राज्य ही ऐसा है जहां पर–कैपिटा इन्कम सबसे ज्यादा है। भारत में और पर–कैपिटा प्लान इनवैस्टमेंट 127 रूपये है जबकि हरियाणा राज्य में एवरेज पर–कपिटा इन्वैस्टमैंट 232 रूपये है। 1971–72 के खर्चे को मिलाकर हमने जो अन्दाजा किया है वह यह है कि हम 160 करोड़ रूपये खर्च कर देंगे यानी तकरीबन 70 प्रतिशत तीन सालों में खर्च कर देंगे जबकि फोर्थ फाईव ईयर प्लान में 225 करोड़ रूपये से भी ज्यादा खर्च करेंगे जो कि हिन्दुस्तान में दूसरे राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा होगा बल्कि काफी ज्यादा होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा प्लाटन के बारे में जैसा कि मैंने अर्ज किया 1968–69 में 42 करोड़ रूपया खर्च किया, 1970–71 में 49.19 करोड़ रूपये खर्च किये हैं और अगले साल 61 करोड़ रूपये से अधिक खर्च करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हर साल 12–13 करोड रूपये प्लान ऐक्सपैंडीचर पर ज्यादा खर्च कर रहें हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है और मैं समझती हूं कि हाउस को सरकार की इस बात के लिए सराहना करनी चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ मेम्बरों का कहना है कि यहां पर बिजली के रेटस बहुत ज्यादा हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि हरियाणा में बिजली की सप्लार्ठ सत्तर फीसदी भाखड़ा से होती है ओर तीन प्रतिशत थर्मल प्लान्टस से पैदा

होती है। जो थर्मल प्लान्टस से बिजली मिलती है उसकी कोस्ट बहुत ज्यादा है। हम एक बहुत अधिक फ्रैस प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं जिसमें 42 प्रतिशत कंजम्पशन एग्रीकलचर सैक्टर में है। हमारी इंडस्ट्रीज की भी बड़ी भारी एक्सपेंशन हुई है इसलिए हमारी बिजली का खर्चा 20 पैसे फी यूनिट आता है और उसमें भी हम सबसिडी देकर 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं। कल आनरेबल मेम्बर श्रीमती चन्द्रावती ने कहा कि बिजली के रेटस बैकवर्ड एरिया तथा ड्रौट अफैक्टिड एरिया में बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए बोर्ड ने यह फैसला किया है कि महेन्द्रगढ़, नाहर, सालावास, लोहारू पर टयूबवैल 100 फुट से ज्यादा गहरे लगते हैं वहां 15 पैसे की बजाए 12 पैसे चार्ज किया जायेगा और जहां 100 फुट से कम गहराई पर लगते हैं वहां 13 पैसे चार्ज किया जाएगा ओर बाकी जगहों पर 15 पैसे ही चार्ज किया जाएगा। वैसे बोर्ड का खर्चा 20 पैसे प्रति यूनिट है। बोर्ड ने देहात में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया है लेकिन देहात में अभी उसका पूरा शौक लोगों में नहीं हुआ है। वहां पर लोग इन्टरनल वायरिंग के लिए कुछ कठिनाई महसूस रकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने फैसला किया है कि इन्टरनल वायरिंग का काम अपने आप किया जाए क्योंकि कई दफा कांट्रेक्टर्ज के जरिए एक्सप्लाएटेशन का जो डर होता है उस पर काबू पाया जाए। अप्रैल के महीने में हमें देहली के एक ऐडीशनल यूनिट से तकरीबन 20 मेगावाट बिजली मिलने वाली है और उससे हमारी बिजली की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। बिजली की कमी जरूर है लेकिन हमारी

कोशिश यही है कि टयूबवैल जो काफी तादाद में चल रहे हैं उनको बिजली पूरी मिल सके जिससे फसल के टाईम में इनको कोई नुक्सान न हो। भाखड़ा में लगभग 60 फुट पानी की कमी के कारण हमें 30 प्रतिशत बिजली की कम सप्लाई हो रही है लेकिन हमें उम्मीद है कि अप्रैल में इस कट को रेस्टोर कर देंगे। हमारी सरकार बैकवर्ड एरियाज की तरफ पूरा ध्यान दे रही है। महेन्द्रगढ़ जिला जो पिछड़ा हुआ जिला है और जहां पर पानी की बहुत कमी है वहां पिछले दो सालों में सात हजार टयूबवैल लगाए गए हैं। हमने वहां पर 66 के.वी. का स्टेशन नारनौल में बनया है और उसकी बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट आफ इन्डिया से मंजूरी मिली है। वे कहते थे कि बिजली की खपत महेन्द्र गढ़ डिस्ट्रिक्ट में इतनी नहीं हो सकेगी। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि 8 मैगावाट का लोड सैक्शन हुआ था उसके अगेन्सट हमारे पास 28 मैगावाट का लोड है और महेन्द्रगढ जिले की इस कमी को बहुत हद तक पूरा करने की कोशिश की है। मैंने इसलिए कहा कि मित्तल साहब ने दूसरे जिलों की बात कही मैं उनके जिले के बारे में बताना चाहती हूं। इरीगेशन के सिलसिले में मित्तल साहब ने कहा कि जो बाकी एरियाज हैं वहां रिग का इन्तजाम नहीं हुआ है माईनर इरीगेशन कारपोरेशन ने एक रिगइम्पोर्ट की है, वह पहुंच गई है, उसको असैम्बल किया जा रहा है। यह रिंग एक हजार फुट से भी नीचे बोरिंग कर सकेगी। जींद जिले में पीन की कमी की बात कही गई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा कुछ हद तक यह सही है। यह कहा जाता रहा हे कि जींद मिले के पानी को निकाल कर जुई

और लोहारू में ले जाया गया है। उस बात का खण्डन पूरी जिम्मेदारी से किया गया है। जींद जिले में पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार के पास कुछ प्रस्ताव हैं जिन पर बहुत तेजी से अमल किया जा रहा है। आप जानती है कि वेर्स्टन जमुना कैनाल की रिमौडलिंग करके हमने उसके पानी की सप्लाई को काफी हद तक बढाया है और हमें उम्मीद है कि अब जींद जिले के पानी की व्यवस्था ठीक हो सकेगी। सर्दियों में देहली पैरेलल लाईन के जरिए, जो हम पक्की बना रहे हैं तकरीबन 150 क्युसिक पानी बढ़ाया जा सकेगा। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा कि जींद के पास कुछ इलाके में मीठे पानी की एक बैल्ट मिली है उस पर पिछले छः महीने में एक्सप्लोरेशन हुई है और उससे काफी आशा नजर आती है। माईनर इरीगेशन कारपोरेशन इस बात की पूरी तहकीकात कर रही है। हम इससे पीन लेकर वहां के लोगों को काफी फायदा पहुंचा सकेंगे। बड़वाला लिंक जो नरवाने के पास जाकर मिलती है उसेस भी अप्रैल के महीने में पंजाब वालों ने हमसे वायदा किया है कि वह अपना बांध बंद कर देंगे और उसे भी हमें कुछ पानी मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त 1973–74 में जब हमें रावी–ब्यास का पानी मिल सकेगा तो उसेस हम जींद जिले की पानी की कमी कुछ हद तक दूर कर सकेंगे। जुई और लोहारू की बात बहुत दफा कही जा चुकी है। मुझे एक बात की खुशी है कि पिछले साल यानी चालू साल में छह करोड रूपये हमने मेजर एंड मीडियम इरीगेशन पर खर्च किए और अगले साल नौ करोड़ रूपए खर्च करेंगे और इस साढे नौ करोड़ में से 50 प्रतिशत खर्चा

ड्रौट अफैक्टिड ऐरियाज के लिये है। वैस्टर्न जमुना कैनाल की रिमौडलिंग पर एक करोड़ रूपया लगाया जायेगा, गुड़गांव कैनाल पर हम एक करोड़ रूपया लगा रहे हैं ओर उसके लिए ओखला पर बैरिज बनाने का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया है। देहली पैरेलल ब्रांच की लाईन के लिए काम शुरू हो रहा है और कोटला के पास जो नौ सक्वेयर मील की एक बड़ी लम्बी चौड़ी लेक है और जो बरबादी का वाईस होती है, उसके पानी को हम सोइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तथा साथ ही साथ उस लेक की जमीन को पानी खत्म हो जाने के बाद राइस सोइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार मुझे फ्लडज प्रोटक्शन की बात भी कहनी है। उसके लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं। हम सब जानते हैं कि यहां एक तरफ बड़ा कहत पड़ता है और दूसरी तरफ फ्लडज आते हैं। पिछले साल यानी चालू साल में इस काम पर 1 करोड़ 90 लाख रूपया खर्च किया है और अगले साल ढाई करोड़ रूपया खर्च कर रहे हैं। कुछ मैम्बर आलोचना करते हैं कि सरकारी मैम्बरों की कंस्टिचुवेंसी में काम किया जाता है और अपोजीशन मेम्बरों का कोई ख्याल नहीं किया जाता। मैं हाउस को बताना चाहती हूं कि सफीदों के एरिया में जहां से सिंगोल साहब आते हैं, फ्लडज आते रहते हैं और उनको रोकने के एिल भी सरकार ने पूरा इन्तजाम किया है। भम्बेवा ड्रेन 20 मील लम्बी हैं जिसकी कौस्ट 20 लाख 60 हजार है। उसके लिए फलड कन्ट्रोल बोर्ड ने मन्जूरी दे दी है ओर उस पर काम शुरू होने वाला है। इससे तकरीबन 30 हजार एकड़ भूमि को राहत मिलेगी। दूसरी बात यह

है कि जींद डिस्ट्रिब्यूटरी नम्बर तीन पर भी काम हो रहा है, नाई नाला अपस्ट्रीम हांसी ब्रांच की रिमौडलिंग की जा रही है जिसके लिए 8.63 लाख की स्कीम एप्रूव हुई है। वहां पर पहले जब फलडज आते थे तो उसेस 50 हजार एकड़ जमीन सबमर्ज हो जाती थी, अब वह जमीन पानी की मार से बच जाएगी और वहां पर लोग फसल पैदा कर सकेंगें राऔली बांध पर 25 लाख रूपया खर्च करके कम्पलीट किया है और फ्लडज को रोका है। इसी तरह कमैछा बांध की 25 लाख की स्कीम है और उस पर काम हो रहा है। कोटला लेक को डिपलीट करने के लिए 65 लाख रूपए की स्कीम है और उस पर काम शुरू होने वाला है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेजर और माईनर इरीगेशन की स्कीमें सरकार की ओर से तो चल रही हैं लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया था हमने कारपोरेशन भी बनाई है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। माईनर इरीगेशन कारपोरेशन जो कि पिछले साल से बनती है बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। हमने कोई दो करोड़ की लागत से 230 टयूबवैल्ज लगाने की स्कीम बनाई है, नारायणगढ़ में 170 टयूबवैल्ज पर काम चल रहा है, साहिबी नदी के साथ साथ 50 टयूबवैल्ज लगाए गए हैं, दादूपुर के बीच में 500 टयूबवैल्ज का प्रोवीजन है। इसके इलावा मूनक तक डबल्यू.जे.सी. के साथ साथ 128 टयूबवैल्ज कम्पलीट किए जा रहे हैं, अगले तीन महीने में यह पूरे होने वाले हैं। 100 टयूबवैल देहली ब्रांच के साथ साथ लगाए जा रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा इतना काम करने के बाद हम पानी की सप्लाई को काफी हद तक पूरा कर सकेंगे। ब्रिजिज

के बारे में हमने तकरीबन अगले साल में इरीगेशन साईड की तरफ से आठ लाख 15 हजार रूपया प्रोवाईड किया है। इसके इलावा बिल्डिंगज एंड रोडज डिपार्टमैंट की तरफ से 54.98 लाख के ब्रिजिज बनने हैं जोकि नदियों पर होंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सड़कों के लिए यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ओर एक प्रैस्टीज रोड़ पंचकुला से अम्बाला की तरफ छः महीने में बनाई है, उसमें जितनी मेहनत की गई उसके बारे में जो मैम्बर उस इलाके के रहने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके ऊपर आठ पुल बनाए हैं और घग्गर पर एक बहुत बड़ा पुल अगले आठ महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। हमने यह बजट बड़े बड़े कैपिटल वर्कस के लिए खासतौर से इलाकों की कमी को दूर करने के एिल बनाया है। जिस वक्त रिआर्गेनाईजेशन हुई थी उस वक्त हरियाणा में 170 गांव को पीने का पानी मिलता था लेकिन 31.3.70 तक हमने 370 विलेजिज कवर कर लिए हैं और इस साल 90 गांवों को पानी मिल जायेगा और अगले साल हम 100 से ज्यादा गांव को और पानी दे देंगे। इसके इलावा पांच करोड़ की लागत की 250 गांवों में नई स्कीमें चल रही हैं। ड्रौट जदा–इलाकों में जो बैनिफिशरीज को साढ़े बारह प्रतिशत शेयर देना पड़ता था वह हमने माफ कर दिया है।

अब मैं इन्डस्ट्रीज की तरफ आती हूं। इसके बारे में हाउस को काफी कफद बताया जा चुका है। हमारी इन्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन ने कई अच्छे अच्छे प्रोजैक्टस अपने हाथ में

लिए हैं। एक कारखाना एक करोड़ रूपए की लागत का गलास का लगेगा, इसके इलावा डेढ़ करोड़ की लागत की बरूरी लगाई जायगी और जींद में ट्रैनिंग का कारखाना लगने वाला है।

चौ. जय सिंह राठी: बरूरी आप कहां पर लगा रहे है?

श्रीमती औम प्रथा जैन: यह मैं आप को बाद में बता दूंगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारे भाई चौ. जयसिंह राठी ने कल बड़े अच्छे लफ्जों में अंग्रेजी बोली और ऐसे लगता था जैसे मास्टर ने अभी सिखा कर भेजा हो (हंसी)

चौ. जय सिंह राठी: अभी सीखी होती तो इतनी अच्छी न होती।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ पता नहीं चलता कि प्रधानमंत्री साहिबा के नाम से वह क्यों खफा हो जाते हैं?

उस दिन कह रहे थे कि उनके जसले पर चालीस लाख रूपया खर्च हो गया और आज फिर नुक्ताचीनी की है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह इस बात को भूल जाते हैं कि वे हमारे देश की प्रधान मंत्री हैं और उनका कोई नेशनल प्रोग्राम है, इसलिए वह जहाँ पर जायेंगी लोग तो उनका स्वागत करेंगे ही। इस बात से उनको खफा नहीं होना चाहिए। छोटे किसानों को ऊपर उठाने के लिए अगर प्रधान मंत्री हमें कोई प्रोग्राम या स्कीम दें तो हमारा फर्ज है कि उस पर तेजी के साथ काम करें। यह कहते हैं इंदिरा

गांधी कम्युनिजम की तरफ बढ़ रही हैं। कम्युनिजम क्या होता है? इस चीज को वह पढ़ लें अच्छे तरीके से। हम चाहते हैं कि जो छोटा किसान है वह ऊपर उठे और अपनी धरती का सम्भाल कर रखे। छोटे किसानों के लिए जो सैंटर से पालिसी आई है उस पर काम शुरू हो गया है और तकरीबन 18 करोड रूपए की कुल मिलाकर उनको मदद मिलेगी जिसमें तीन करोड़ रूपया गवर्नमैंट आफ इन्डिया ने दिया है। सैंटर की तरफ से सबयार्जनल स्कीम अम्बाला और हिसार जिले के लिए आई है जिसके लिए दो करोड़ रूपया सटर के दिया है। हम चाहते हैं कि छोटे किसानों को न्याय मिले। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा हमने बैकवर्ड क्लासिज ओर एग्रीकल्चर लेबर वैलफेयर की कई स्कीमें बजट में रखी हैं। हमने स्लम कलियरस के लिए भी वायदा किया है। हम हाउसिंग डिवैल्पमैंट बोर्ड की तरफ से मकान बना कर उनको देंगे और झुग्गी डवेलर्ज के लिए भी इन्तजाम किया जा रहाहै (प्रशसा)।

चौ. जय सिंह राठी: यह आप के स्लोगन्ज ही हैं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आज तक तो स्लोगन्ज वाली बात नहीं की। हमने तो ऐसे सडत्रकें तो नहीं बनाई कि बीच में अगर अपोजीशन वाले का गांव आ गया तो उसको छोड़ दिया और बिजली देने में भी अपोजीशन वालों के गांव को नजरअन्दाज कर दिया। हमने तो सबको एकसा ट्रीट किया है ओर यह सारी सहूलियतें दी हैं। अगर आपका यह खयाल हो कि आप इस तरह के नारे लगा कर या ऐसा लगत प्रोपोगंडा करके पार्लियामैंट के

इलैक्शन में कामयाबी हासिल कर लेंगे तो आपकी वह उम्मीद पूरी नहीं होगी। हमने इन्डस्ट्रियल लेबर के लिए भी मकान बना कर देने का आश्वासन दिया है। यहां पर ऐम्पलायमैंट के बारे में काफी चर्चा हुई। इसके बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि हरियाणा स्टेट एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले एक्पलायमैंट पोटैंशल को बढ़ाया है। आज हमारे प्रान्त में 50 हजार से भी ज्यादा लेबर सड़कों पर काम कर रही है। मैंने पिछले सला के फिगर्ज दिये थे कि कितने ओवरसियर और इन्जीनियर लगाये हैं। इरीगेशन की तरफ से जो नई स्कीमें चालू हुई हैं उसमें हमने 500 नए ओवरसियर रखे हैं, फिर पब्लिक हैल्थ में 150 नए ओवरसियर रखे हैं, बी एण्ड आर में नियुक्त किये गये ओवरसियर्ज की संख्या 800 से ज्यादा है। (इसी समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) हमने सकिल्ड और अन–सकिल्ड लेबर यानी दोनों को ही ऐम्पलायमैंट दी है। यह हरियाणा स्टेट देश मैं सबसे पहली स्टेट है जिसने नैशनल लेबर कमीशन की सिफारिशात के तहत और मुताबिक लेबर को तनख्वाह देने का फैसला किया है। अनसकिल्ड लेबर को सौ रूपए मिनिमम वेज देना तय किया है। मैंने आप को बताया है कि हरिजनों के लिए हम ने बजट में हाउसिंग स्कीम के लिए पैसा रखा है लेकिन इसके साथ–साथ हमने एक और चीज की है कि हरिजनों के लिए हाउसिंग लोन्ज के लिए जो 20 लाख रूपया रखा है उस पर चाार प्रतिशत सूद होगा जो कि आम तौर पर सात प्रतिशत होता है। सात प्रतिशत के हिसाब से अगर कोई तीन हजार रूपया लोन लेता है तो बीस साल में 3600 रूपय सूद का

बन जाता है लेकिन अब चार प्रतिशत से 1900 रूपए रह जायेगा और इस तरह से हमने हरिजनों को 16/17 सौ रूपए की डिडन सबसिडी दी है। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में एक बात रह गई है। सिंगोल साहब ने कहा कि अमैंडमैंट लानी पड़ेगी लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अमैंडमैंड की जरूरत नहीं यह कात नोटिफिकेशन से हो जाएगा और सरकार ने जो कुछ कहा है वह करने के लिए कहा है।

एक आवाज: बरूरी के बारे मे नहीं बताया कहां लगेगी?

श्रीमती ओम प्रभा जैन: वह मुरथल में लगा रहे हैं।

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 27181570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 19-General Administration.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 50861690 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 31-Agriculture.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 2056000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 95-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 11710300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 35. Industries.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 28351000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 40537310 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 42-Multipurpose River Schemes.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 45143850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) (44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)

That a sum not exceeding Rs. 24519750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head Charges on Irrigation Establishment.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 53000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 119130190 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 45964840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 50-Public Works.

That a sum not exceeding Rs. 17430600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head charges on Building and Roads Establishment.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 3212580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 52-Capital Outlay on Public Works.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 221604000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 103-Capital Outlay on Public Works.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 11018940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 9-Land Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 925900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 10-State Excise Duties.

That a sum not exceeding Rs. 678400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 11-Taxes on Vehicles.

That a sum not exceeding Rs. 3447490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 12-Sales Tax.

That a sum not exceeding Rs. 2221900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 13-Other Taxes and Duties.

That a sum not exceeding Rs. 391260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 14-Stamps.

That a sum not exceeding Rs. 51580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 15-Registration Fees.

That a sum not exceeding Rs. 2422900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 18- Parliament State/Union Territory.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 4881010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 21-Administration of Justice.

That a sum not exceeding Rs. 4828170 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 22-Jails.

That a sum not exceeding Rs. 45745280 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 23-Police.

That a sum not exceeding Rs. 455970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 25-Supplies and Disposals.

That a sum not exceeding Rs. 2371860 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 26-Miscellaneous Departments.

That a sum not exceeding Rs. 56700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 27-Scientific Department.

That a sum not exceeding Rs. 202521040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 28- Education.

That a sum not exceeding Rs. 43934300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 29-Medical.

That a sum not exceeding Rs. 62719100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 30-Public Health.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 19666830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 33-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 8436400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 34-Co-operation.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 15989870 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs. 14257490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 38-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 11650440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 39-Miscellaneous, Social and Development Organisations.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 101799350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 57-Roads and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 23000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 64-Famine Relief.

That a sum not exceeding Rs. 12503500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 65-Pension and other Retirement Benefits.

That a sum not exceeding Rs. 37600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 67-Privy Purses and Allowances of Indian Rules.

That a sum not exceeding Rs. 8170850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 68-Stationery and Printing.

That a sum not exceeding Rs. 10408090 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 70-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 44320570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 71-Miscellaneous.

That a sum not exceeding Rs. 57250 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the

course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 76-Other Miscellaneous compensations and Assignments.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 999500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 109-Capital Outlay on Road and water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 20844140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a sum not exceeding Rs. 290000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 120-Payment of Commuted Value of Pensions.

That a sum not exceeding Rs. 513038710 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head 124-Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

The motion was carried

That a sum not exceeding Rs. 191115300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head Loans to Local Funds-Private Parties, Loans to Government Servants.

That a sum not exceeding Rs. 10517280 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1971-72 in respect of the charges under head Inter-State Settlement.

The motion was carried

12.37 P.M.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2 P.M. today. (The Sabha then adjourned till 2 P.M. on Tuesday, the 16th February 1971.)

ANNEXURE

(Please see footnote on page (8)5

Loans to families possessing less than 5 Acres of lands.

***1156 Sh. Randhir Singh**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the total number of families possessing less than 5 standard acres of land in the State to whom loans for Tractors, tubewells and small scale industries, controlled by the Department have been advanced during the year, 1970?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल):

क्रमांक		नम्बर	राशि (रूपये लाखों में)
1	ट्रैक्टर	69	
2	टयूबवैल	1968	7.70
3	लघु उद्योग		122.09